



मंत्रालयों और विभागों की वर्षांत समीक्षा

(भाग-2)

(पूरक डॉक्यूमेंट)

विषय-सूची

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs).....	3
2. राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Revenue (Ministry of Finance)}.....	5
3. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Investment and Public Asset Management (Ministry of Finance)}.....	7
4. वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Financial Services (Ministry of Finance)}	8
5. व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Expenditure (Ministry of Finance)}.....	9
6. आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Economic Affairs (Ministry of Finance)}	12
7. लोक उद्यम विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Public Enterprises (Ministry of Finance)}	14
8. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) {Department of School Education & Literacy (Ministry of Education)}.....	15
9. संसदीय मामलों का मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs).....	15
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region: MDoNER).....	16
11. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power).....	19
12. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय {Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)}.....	21
13. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises).....	23
14. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)}.....	26
15. पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Department of Pension & Pensioners' Welfare (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions)}.....	27
16. केंद्रीय सूचना आयोग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Central Information Commission (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions)}	27
17. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)	27
18. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)	28
19. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)	30
20. अंतरिक्ष विभाग (Department of Space)	30
21. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) {Department of Biotechnology (Ministry of Science & Technology)}.....	31

22. परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)	33
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science)	33
24. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) {Council of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science & Technology)}	34
25. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)	35
26. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)	35
27. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare)	36
28. आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH)	39
29. फार्मास्यूटिकल्स विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) {Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers)}	40
30. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) {Department of Chemicals and Petrochemicals (Ministry of Chemicals and Fertilizers)}	40
31. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (Ministry of Food Processing)	41
32. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) {Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)}	42
33. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) {Department of Social Justice & Empowerment (Ministry of Social Justice & Empowerment)}	43
34. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) {Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Ministry of Social Justice & Empowerment)}	43
35. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)	44
36. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)	45
37. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)	46
38. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) {Department of Drinking Water and Sanitation (Ministry of Jal Shakti)}	46
39. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) {Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Ministry of Jal Shakti)}	47
40. पत्तन, पोत-परिवहन और जल-मार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports Shipping and Waterway)	47

नोट: इस डॉक्यूमेंट में वर्ष 2023 के संदर्भ में प्रेस सूचना ब्यूरो पर प्रकाशित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षा का संक्षिप्त ब्योरा प्रदान किया गया है। इसमें विभिन्न सरकारी क्षेत्रों की पहलों, प्रगति और उपलब्धियों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट से UPSC के इंटरव्यू की तैयारी के लिए तेजी से रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, इसका उपयोग करके अभ्यर्थी अपने नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं।

भाग-2: इसमें भारत सरकार के 40 मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षाएं शामिल हैं, जैसा कि विषय-सूची में भी दिया गया है। भारत सरकार के 19 मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षा का संक्षिप्त ब्योरा भाग-1 में पहले से उपलब्ध कराया जा चुका है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs)

विषय	पहलें/ प्रगति/ उपलब्धियां
कानूनों/ दिशा-निर्देशों में परिवर्तन	- औपनिवेशिक युग के पुराने "जेल अधिनियम, 1894" की समीक्षा और बदलाव के बाद मॉडल जेल अधिनियम, 2023 तैयार किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू किया गया। - आपराधिक मामलों से जुड़े कानूनों (दंड विधि) में सुधार के लिए भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 बनाए गए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 बनाया गया।
जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू किया गया। - सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय को बरकरार रखा। - केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 2021 में अधिसूचित की गई। G-20 पर्यटन कार्य-समूह की तीसरी बैठक मई 2023 में श्रीनगर में आयोजित की गई। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (WPR)¹ योजना: पात्र WPR परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता लघु व्यवसाय चलाने या भूमि-आधारित अन्य आर्थिक कार्यों को करने के लिए दी जाती है।
लद्दाख	- नई "लद्दाख होम स्टे नीति, 2023" अधिसूचित की गई है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को ठहरने के दौरान घर जैसा एहसास दिलाना है। - नुब्रा, चांगथांग और जांस्कर के ऑफ ग्रिड क्षेत्रों को छोड़कर लद्दाख के शेष सभी क्षेत्रों में डीजल इंजनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र	- मार्च 2023 में, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)² के तहत नागालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों को कम किया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच काफी समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। - भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/ दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (DNLA/ DPSC) के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय फॉरेंसिक-विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के गुवाहाटी (असम) परिसर की आधारशिला रखी गई। - भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। - भारत सरकार, असम सरकार तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा/ ULFA) के प्रतिनिधियों के बीच दिसंबर 2023 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

¹ West Pakistani Refugees

² Armed Forces Special Powers Act

वामपंथी उग्रवाद	11 संयुक्त टास्क-फोर्स और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) स्थापित किए गए हैं। इनमें राज्य पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्यों के विशेषीकृत पुलिस बलों को तैनात किया गया है। - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास योजना के तहत, 3 ITIs और 11 कौशल विकास केंद्रों (SDCs) ने काम करना शुरू कर दिया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा/ पुलिस को मजबूत बनाना	- संगठन/ व्यक्ति/ एसोसिएशन को आतंकवादी घोषित करना 2023 में चार संगठनों को 'आतंकवादी संगठन', सात व्यक्तियों को 'आतंकवादी' और तीन संगठनों को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया गया। - आतंकवादी संगठन हैं: द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), पीपुल्स एंटी-फासिस्ट-फ्रंट (PAFF), जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF), तथा खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF)। - गैर-कानूनी संगठन हैं: जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP), मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट), और तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर (TeH)। - विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम³, 1967 के अंतर्गत संगठनों/ व्यक्तियों/ एसोसिएशन को आतंकवादी घोषित किया जाता है। - जनवरी 2023 से नेशनल क्राइम रिकार्ड्स चेक (NCRC) पोर्टल शुरू किया गया। - जेलों में कैदियों के प्रबंधन में मदद के लिए आधार सत्यापन की व्यवस्था शुरू की गई। - मार्च 2023 में नेशनल डेटाबेस ऑन ह्यूमन ट्रेफिकिंग ऑफेंडर्स (NDHTO) पोर्टल और नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर्स ऑफ फॉरिन ओरिजिन (NDOFO) पोर्टल लॉन्च किए गए। ये पोर्टल जेलों तथा "क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेफिकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (CCTNS)" पर उपलब्ध डेटा के आधार पर तैयार किए गए हैं।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)	- CAPFs में भर्ती के लिए कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने को मंजूरी दी गई। - CAPF और NDRF के कर्मियों के लिए मेस/कैंटीन में मिलेट्स (श्री अन्न) शामिल करने का निर्णय लिया गया।
मादक पदार्थों की तस्करी	- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। - गृह मंत्रालय ने 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है; संस्थागत संरचना को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना।
साइबर सुरक्षा	- द्वारका (गुजरात) में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (NACP) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई। - बेंगलुरु में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स शुरू की गई। इनका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से देश की पुलिसिंग व्यवस्था में एक नया आयाम जोड़ना है। - जुलाई, 2023 में नॉन-फजिबल टोकन (NFTs), AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G-20 सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सीमा प्रबंधन	- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" को मंजूरी दी। - अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' शुरू किया गया। - बिहार के अररिया में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर नवनिर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया।

³ Unlawful Activities (Prevention) Act

आपदा प्रबंधन	- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। - जुलाई 2023 में "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की गई। 'चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों' के लिए शहरी बाढ़ पर पहली शमन परियोजना को मंजूरी दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम/सम्मेलन	भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) तथा नाइजीरिया की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी (NDLEA) के बीच नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रीकर्सर केमिकल्स तथा संबंधित मामलों में अवैध तस्करी की रोकथाम पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
अन्य महत्वपूर्ण पहलें/कार्यक्रम	- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वीप (अंडमान-निकोबार) पर नेताजी को समर्पित "राष्ट्रीय स्मारक" के मॉडल का अनावरण किया गया। - ई-ऑफिस कार्यान्वयन के तहत, गृह मंत्रालय की लगभग 50% फाइलें अब ई-फाइल के रूप में उपलब्ध हैं। - अप्रैल 2023 में युगांडा के जिंजा में भारत के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया। - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) टीम को "श्रेणी 1-ई-गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन योजना 2023" के तहत राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) के लिए "गोल्ड अवार्ड" मिला।

2. राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Revenue (Ministry of Finance)}

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)	- प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्थिर वृद्धि: वित्त वर्ष 2023-24 में (30 नवंबर, 2023 तक) सकल संग्रह वित्त-वर्ष 2022-23 की समान अवधि के सकल संग्रह से 17.7% अधिक था। - शीघ्र रिफंड: 01 अप्रैल, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक 2.03 लाख करोड़ रुपये की रिफंड राशि जारी की गई। - इनकम टैक्स रिटर्न (ITR): 30 नवंबर, 2023 तक सभी असेसमेंट ईयर (AYs) के लिए 7.97 करोड़ ITR फाइल किए गए। - करदाता आउटरीच: करदाताओं को अपने ITR दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ईमेल और SMS के माध्यम से सूचना देने के अभियानों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए। - स्टार्टअप्स के लिये व्यवसाय करने में आसानी: TIN 2.0 नामक एक नया ई-पे टैक्स भुगतान प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया। - फेसलेस प्रोसेसिंग: 22 नवंबर, 2023 तक, 4.58 लाख फेसलेस असेसमेंट पूरे किए गए।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)	- वस्तु एवं सेवा कर (GST): - धोखाधड़ी वाले तत्वों को GST प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पंजीकरण आवेदन की रिस्क रेटिंग की गई। - आवेदकों के व्यवसाय के लिए जियो-टैगिंग की सुविधा शुरू की गई। - ऐसे मामलों में जहां लगातार 6 महीने की अवधि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, उनके लिए सिस्टम-बेस्ड रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन की शुरुआत की गई। - धोखाधड़ी करने वाले करदाताओं को अनुचित/अपात्र रिफंड की स्वीकृति रोकने के लिए रिफंड आवेदनों की जोखिम रेटिंग की शुरुआत की गई। - फर्जी पंजीकरण के खिलाफ एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया। - विसंगतियों की सूचना देने के लिए प्रणाली आधारित तंत्र का निर्माण किया गया।

- अपंजीकृत व्यक्तियों को अस्थायी पंजीकरण करने और रिफंड के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए कॉमन पोर्टल पर नए फीचर की शुरुआत की गई।
- नकदी प्रवाह में सुधार के उपाय: किसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि को एक अलग व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई।
- GST परिषद की 47वीं बैठक: अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजीशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (ECOS) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति देने की सिफारिश की गई।
- 20 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा विलंबित फाइलिंग के लिए विलंब शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया।
- B2B (बिजनेस टू बिजनेस) लेनदेन हेतु ई-चालान प्रणाली के लिए वार्षिक कुल कारोबार की सीमा को पहले के 500 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- उन मामलों में सर्वोत्तम निर्णय असेसमेंट आदेशों के आधार पर वापसी के लिए सशर्त माफी योजना शुरू की गई है, जहां ऐसे असेसमेंट की तय तारीख से 30 दिनों के भीतर वैध रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- 'अकाउंट एग्रीगेटर' को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया गया है जिनके साथ पंजीकृत व्यक्ति/करदाता के डेटा को उनकी सहमति के आधार पर कॉमन पोर्टल के साथ साझा किया जा सकता है।
- GST अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सरल और गैर-आपराधिक बनाने के लिए CGST अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं।
- GST अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन CGST अधिनियम, 2017 में संशोधन के माध्यम से किया गया था।
- इसरो, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST छूट निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं तक बढ़ा दी गई है ताकि स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जा सके।
- GST परिषद की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने का निर्णय लिया गया।
- GST परिषद की 52वीं बैठक में परिषद ने सरकारी प्राधिकारियों को आपूर्ति की जाने वाली जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को GST से छूट देने की सिफारिश की।
- मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लिकेशन पर B2C (बिजनेस टू कंज्यूमर) चालान अपलोड करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए चुनिंदा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई।
 - इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीदारी के दौरान GST चालान की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक लेनदेन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- व्यावसायिक परिसरों के भौतिक सत्यापन के लिए आवेदक की उपस्थिति की आवश्यकता को दूर करने के लिए CGST नियम, 2017 में संशोधन किया गया। यह संशोधन उच्च जोखिम वाले मामलों में भी लागू होगा जहां आधार द्वारा प्रमाणन के बाद भी भौतिक सत्यापन की जरूरत है।
- कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू किए गए।
- ऐसे मामलों में जहां स्वीकार्य समय अवधि के भीतर अपील दायर नहीं की जा सकी है, वहां डिमांड ऑर्डर्स के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना की शुरुआत की गई।
- एक वर्ष पूरा होने के बाद औपबन्धिक रूप से संलग्न संपत्ति की स्वतः पुनर्बहाली करने का प्रावधान किया गया।

	- सीमा शुल्क: - विनियामक और नीतिगत पहलें - वस्त्र और कृषि क्षेत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया। - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराधों के मामले में विनियामक अनुपालन को नियमानुकूल बनाना: गिरफ्तारी वाले प्रावधानों में सामान, सोने की सीधी तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए प्रारंभिक मूल्य सीमा को 20 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया। - बंदरगाहों पर सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परीक्षण परिभाषा का प्रावधान किया गया। - CBIC ने कई बंदरगाहों और एयर कार्गो परिसरों में 24x7 कस्टम क्लियरेंस की सुविधा दी है। - CBIC ने अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल्स (ICTs) के माध्यम से आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक सरलीकृत विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया। - डाक मार्गों के माध्यम से निर्यात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और निकासी की सुविधा। - तकनीकी पहलें: - भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ICEGATE) 2.0 शुरू की गई। - फेसलेस असेसमेंट के तहत बिल ऑफ एंट्री क्लियरेंस में देरी से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए एनोनीमाइज़्ड एस्केलेशन मेकेनिज्म। - सरकार के पास अग्रिम जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जिसका उपयोग इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। - RODTEP के लिए ई-स्क्रिप्ट प्रणाली: घरेलू उद्योग को विदेशों में समान अवसर प्रदान करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने हेतु। - अवसंरचनात्मक पहलें: - निर्यात कंटेनरों के रुकने के समय को कम करने और बंदरगाह पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए कोलकाता बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्री-गेट प्रोसेसिंग सुविधा शुरू की गई। - सीमा शुल्क की आंतरिक परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं (CRCL) का अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण किया गया, जिससे आयात और निर्यात को तीव्र मंजूरी मिलती है। - जहाज़ बोर्डिंग अधिकारियों को उपयोग के लिए कैमरा युक्त जैकेट प्रदान की गई हैं।
--	---

3. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Investment and Public Asset Management (Ministry of Finance)}

CPSEs में मूल्य सृजन	जनवरी 2021 में नई PSE नीति की घोषणा के बाद से, NSE, CPSE और BSE CPSE सूचकांकों ने नवंबर 2023 तक क्रमशः 160.49% तथा 128.66% के रिटर्न के साथ बड़े अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के IPO के लिए मंजूरी दी।
बिक्री हेतु प्रस्ताव (OFS)	जनवरी 2023 से HAL, कोल इंडिया लिमिटेड, RVNL, SJVN लिमिटेड और HUDCO में 'बिक्री की पेशकश' (OFS) लेन-देन किए गए।
सतत लाभांश नीति का कार्यान्वयन	- DIPAM ने नवंबर 2020 में 'सतत लाभांश नीति' के बारे में एडवाइजरी जारी की थी। - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा लाभांश भुगतान पिछले 3 वर्षों में बढ़ा है।

	चालू वित्त वर्ष के दौरान 04.12.2023 तक सरकार को CPSEs से लाभांश प्राप्तियों के रूप में 26,644 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
रणनीतिक विनिवेश	मौजूदा समय में जारी लेन-देनों के लिए IDBI बैंक लिमिटेड, PDIL, HLL लाइफकेयर लिमिटेड, NMDC स्टील लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और BEML लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की जाती हैं।

4. वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Financial Services (Ministry of Finance)}

उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (EASE) सुधार {Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Reforms}	EASE की अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जोखिम आकलन में सुधार, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPAs) प्रबंधन, वित्तीय समावेशन को अधिक गहरा बनाने, उन्नत ग्राहक सेवा, डिजिटल बदलाव की दिशा में पहल, खुदरा और MSMEs क्रेडिट ऑफ टेक आदि से संबंधित है। - EASE सुधारों का संचालन भारतीय बैंक संघ की EASE संचालन समिति द्वारा किया जाता है। EASE 6.0 (वित्त वर्ष 2024) की संकल्पना निम्नलिखित 4 विषयों के अंतर्गत 22 कार्रवाई बिंदुओं के साथ की गई थी- - डिजिटल सक्षमता के साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करना। - डिजिटल और विश्लेषण आधारित व्यवसाय में सुधार करना। - तकनीक और डेटा सक्षम क्षमता निर्माण करना। - लोगों का विकास करना और मानव संसाधन संचालन को बढ़ाना।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) में NPAs	SCBs का सकल NPA अनुपात 31 मार्च, 2019 के 9.07% से घटकर 31 मार्च, 2023 तक 3.87% हो गया था। - इसके अलावा, SCBs के मामले में वित्त वर्ष 2018-19 में नया NPA 3.73 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 1.78 प्रतिशत रह गया था। 13 सितंबर, 2023 तक राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने 1,69,910 करोड़ रुपये के कुल ऋण जोखिम वाले 30 खातों के लिए बाध्यकारी ऑफर जारी किया है। SCBs का निवल NPA मार्च 2022 के 1.67 प्रतिशत से घटकर मार्च 2023 में 0.95 प्रतिशत रह गया। इससे बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा है। - SCBs के मामले में कर्ज की तुलना में प्रोविज़न कवरेज अनुपात मार्च 2022 के 86.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 90.9 प्रतिशत के मजबूत स्तर पर पहुंचने से SCBs का लचीलापन बेहतर हुआ है।
डिजिटल भुगतान	जुलाई 2023 से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का कार्य MeitY से वित्तीय सेवा विभाग (DFS) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

	- डिजिटल भुगतान की प्रगति: - वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 15 अक्टूबर, 2023 तक 8,513 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन-देन किए जा चुके हैं। - वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान लेन-देन में 62 प्रतिशत लेन-देन BHIM-UPI के जरिए किए गए। - अगस्त 2023 में, BHIM-UPI ने पहली बार एक महीने में 1,000 करोड़ से अधिक लेन-देन दर्ज किए थे। - वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 में संवाद केंद्रित भुगतान (हेलो यूपीआई एवं बिलपे कनेक्ट) तथा यूपीआई लाइट एक्स की शुरुआत की गई थी।
वित्तीय समावेशन	- प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY): 04 अक्टूबर, 2023 तक PMJDY खातों की संख्या 50.63 करोड़ थी। - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 04 अक्टूबर, 2023 तक PMJJBY के तहत संचयी नामांकन की संख्या 18.19 करोड़ थी। - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 04 अक्टूबर, 2023 तक PMJJBY के तहत संचयी नामांकन 40.29 करोड़ था। "मुद्रा- फंडिंग द अनफंडेड": योजना की शुरुआत के बाद से 43.74 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। - लगभग 69% ऋण महिला उद्यमियों को और 51% ऋण SC/ST/OBC श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं। - स्टैंड-अप इंडिया योजना: 24 नवंबर, 2023 तक इस योजना के तहत लगभग 47,073 से अधिक SC/ST और महिला उधारकर्ता लाभान्वित हुए थे। - अटल पेंशन योजना (APY): योजना अंतर्गत लगभग 5.97 करोड़ कुल सकल नामांकन दर्ज किए गए थे।
कृषि ऋण और KCC	- जमीनी स्तर पर कृषि ऋण (GLC) - पिछले 9 वर्षों में कृषि ऋण में लगभग 13% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। - KCC योजना: 30 जून, 2023 तक सक्रिय KCC खातों की कुल संख्या 7.36 करोड़ थी।

5. व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Expenditure (Ministry of Finance)}

डेटा गैप इनिशिएटिव	- वर्ष 2009 में G-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट से सामने आए आंकड़ों के अंतर को दूर करने के लिए 'डेटा गैप इनिशिएटिव' (DGI) का समर्थन किया था। - लेखा महानियंत्रक (CGA) ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को 'आरईडी (RED)' से 'एएमबीआईआर' (AMBER) में बदल दिया है।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)	- PFMS भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के लाभार्थियों के लिए DBT को सक्षम बनाता है। - राज्य स्तर की योजनाओं सहित 1,016 योजनाओं में भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाता है।

	• PFMS-एक्सटर्नल सिस्टम इंटीग्रेशन: भारत में 113 से अधिक भुगतान प्रणालियां PFMS के साथ एकीकृत हैं। • PFMS पर लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (CS) हैं। साथ ही, RBI सहित सभी प्रमुख बैंकों का PFMS के साथ इंटरफेस है। • LPG सब्सिडी की पहल/ PAHAL (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) योजना के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नवंबर 2023 तक 76.95 करोड़ लेन-देनों के माध्यम से 8,142.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। • राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को उनकी क्रेडिट स्थिति जानने में सक्षम बनाने के लिए, PFMS ने छात्रवृत्ति भुगतान कार्यक्षमता के लिए 'ट्रैक एनएसपी पेमेंट' स्टेटस विकसित और लागू किया है।
सिंगल नोडल अकाउंट (SNA)	• SNA कुशल नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करता है और प्रणाली में लगने वाले समय को कम करता है। • सभी 31 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के कोषागारों में पूर्ण निर्बाध राजकोषीय एकीकरण (TI) हासिल किया गया है। • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए PFMS के SNA मॉड्यूल पर 4,396 योजनाएं शामिल की गई हैं। • राज्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी स्टैंडअलोन प्रणालियों को भी PFMS के साथ MIS के लिए एकीकृत किया गया है।
सेंट्रल नोडल अकाउंट (CNA)	• PFMS के सेंट्रल नोडल अकाउंट (CNA) मॉड्यूल के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कोष के प्रवाह की निगरानी और ट्रैकिंग जा रही है। • CNA कार्यान्वयन मॉडल-1 {सकल बजटीय अनुमान (GBE) 500 करोड़ रुपये से अधिक} ○ PFMS पर अब तक मॉडल-1 के तहत 57 योजनाएं शामिल की जा चुकी हैं। • CNA कार्यान्वयन मॉडल-2 (500 करोड़ रुपये से कम GBE वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए) ○ PFMS पर अब तक मॉडल-2 के तहत 210 योजनाएं शामिल की जा चुकी हैं।
PFMS के साथ ई-ग्राम स्वराज (eGram Swaraj) इंटरफेस	• सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS), ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों को निर्बाध भुगतान प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती है। • PFMS ई-ग्राम स्वराज इंटरफेस 2.78 लाख (जिला, ग्राम, ब्लॉक पंचायत और जनजातीय स्थानीय निकाय) में से 2.63 लाख से अधिक पंचायतों के साथ उनके भुगतान लेन-देन के लिए एकीकृत है।
सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (GIFMIS) वर्टिकल	• GIFMIS सरकार के अन्य सभी प्रकार के भुगतानकर्ताओं की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है। • भुगतान के अंतिम डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में, PFMS प्लेटफॉर्म पर GIFMIS के तहत ई-बिल मॉड्यूल विकसित किया गया था। • GIFMIS को 52 मंत्रालयों/ विभागों और विधान सभा रहित 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 447 वेतन व लेखा इकाइयों में लागू किया गया है।
सिंगल नोडल अकाउंट (SNA)-स्पर्श (SPARSH)	• SNA-स्पर्श को GIFMIS के तहत PFMS प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 'जस्ट-इन-टाइम' यानी बिल्कुल समय पर निधि जारी करने की सुविधा पर केंद्रित है। वर्तमान में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा है।

	• शामिल राज्य: राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा। • कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में प्रायोगिक आधार पर जिन राज्यों में शीघ्र लॉन्च होने वाला है: तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश। • प्रायोगिक आधार पर चरण 1 के लिए लागू SNA स्पर्श योजनाएं: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G)।
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) की पहलें	• दीर्घायु ऐप विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए- SSA (स्पेशल सील ऑथॉरिटीज़) डाउनलोड करना, शिकायतों की स्थिति, पेंशन खाते में पिछले 24 लेन-देनों का विवरण आदि। • केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों की शिकायतों के तत्काल और त्वरित समाधान के लिए 2023 में दो वर्चुअल पेंशन अदालतें आयोजित की गई थीं। • CPAO में त्वरित शिकायत समाधान के लिए अर्धसैनिक बलों के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों हेतु एक अलग डेस्क स्थापित किया गया है।
पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना	• वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों के अनुरोध पर इस योजना को फिर से डिजाइन और विस्तार किया गया। • आठ क्षेत्रों में प्रोत्साहन के रूप में 30,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन सहित 1.30 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24	• केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राज्यों को 1,00,000 करोड़ रुपये (शर्त रहित) आवंटित किए गए हैं। • पुराने वाहनों को स्कैप करने के लिए प्रोत्साहन देना: राज्य सरकार के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों और एंबुलेंसों को स्कैप करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। • शहरी नियोजन सुधार: सतत शहरीकरण के लिए किफायती आवास, व्यापक गतिशील परिवहन को बढ़ावा देने और ब्लू-ग्रीन बुनियादी ढांचे के संरक्षण के लिए 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। • शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार: शहरों की साख में सुधार करने और संपत्ति कर प्रशासन सुधारों को प्रोत्साहित करके तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर उपयोगकर्ता शुल्क की रिंग-फेंसिंग करके उन्हें नगरपालिका बॉण्ड्स हेतु तैयार करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। • शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उनके हिस्से में पुलिस कर्मियों के लिए आवास: शहरी क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास सुविधा बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। • यूनिटी मॉल्स का निर्माण: राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। • बच्चों और किशोरों के पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना: पंचायत और वार्ड स्तर पर राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों तक पहुंच के लिए बुनियादी ढांचे के साथ एक भौतिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। • RBI के ई-कुबेर मॉडल का उपयोग करते हुए 'जस्ट-इन-टाइम' रिलीज: इसके तहत, कोई भी राज्य RBI की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से 'जस्ट-इन टाइम' मॉडल के तहत लाई गई योजना के केंद्र वाले हिस्से के 10 प्रतिशत के बराबर प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होगा।

वर्ष 2023-24 के लिए निवल उधारी सीमा (NBC)	- पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों हेतु सामान्य NBC सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3 प्रतिशत तय की गई है। - राज्यों को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (NSDL)/ ट्रस्टी बैंक के साथ उनके कर्मचारियों के योगदान के नियोक्ता और कर्मचारी वाले हिस्से के बराबर अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है।
विद्युत क्षेत्रक में प्रदर्शन से जुड़े GSDP का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार	15वें वित्त आयोग ने विद्युत क्षेत्रक में राज्यों को सामान्य NBC से ऊपर GSDP के 0.50 प्रतिशत के बराबर प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार सीमा की सिफारिश की है।
विवाद से विश्वास योजना	- विवाद से विश्वास योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। - विवाद से विश्वास (MSMEs के लिए राहत): कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में असमर्थ रहने वाले MSMEs को राहत प्रदान की गई थी। - विवाद से विश्वास-II (अनुबंध संबंधी विवाद): यह योजना केंद्र सरकार के लंबित सार्वजनिक खरीद से जुड़े अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए शुरू की गई थी।

6. आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Economic Affairs (Ministry of Finance)}

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGBs)	- इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकार की समग्र बाजार उधारी के एक हिस्से के रूप में हरित अवसंरचनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। - सरकार ने 2023 में SGBs जारी करके 27 दिसंबर, 2023 तक 16,000 करोड़ रुपये जुटाए थे।
बचत योजनाएं	- आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC) योजना शुरू की थी। - वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। - डाकघर की 'मासिक आय बचत योजना' के लिए अधिकतम जमा की सीमा- - एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और - संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। - सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3.2 करोड़ खाते सक्रिय हैं।
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF)	- NIIF ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) के साथ संयुक्त रूप से अपने पहले द्विपक्षीय कोष के रूप में भारत-जापान कोष की शुरुआत की है। - इसका उद्देश्य मल्टी बिलियन डॉलर के ग्रीन-ट्रांजीशन कोष की स्थापना की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC) के साथ मिलकर काम कर रहा है।
भारत की G-20 की अध्यक्षता के तहत G-20 फाइनेंस ट्रैक, 2023	- भारत की G-20 की अध्यक्षता के दौरान G-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स (FMCBG) की 4 बैठकों और डिप्टी गवर्नर्स की 5 बैठकों सहित कुल 35 बैठकें आयोजित की गई थी। - G-20 फाइनेंस ट्रैक के मुख्य परिणामों पर एक नजर: - इसके तहत बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को मजबूत करने पर G-20 देशों के स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की गई।

	- क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर IMF-वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) का सिंथेसिस पेपर जारी किया गया। - समयबद्ध रूप से पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। - डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और नई वित्तीय समावेशन कार्य योजना 2024-26 के माध्यम से वित्तीय समावेशन व उत्पादकता लाभ को बढ़ावा देने के लिए G-20 देशों द्वारा नीतिगत सिफारिशें जारी की गईं। - वैश्विक ऋण प्रणाली की कमजोरियों का प्रबंधन: G-20 देशों ने ऋण समाधान के लिए सामान्य फ्रेमवर्क में उल्लिखित सभी प्रावधानों को बनाए रखने तथा पूर्वानुमानित, समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित तरीके से इनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। - ऋण पुनर्गठन प्रयासों में तेजी लाने के लिए 2023 में ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (GSDR) की शुरुआत की गई थी। यह IMF, विश्व बैंक और भारत की अध्यक्षता में G-20 की एक संयुक्त पहल है। - G-20 सतत वित्त तकनीकी सहायता कार्य योजना (TAAP)। - G-20 बुनियादी ढांचा कार्यकारी समूह निम्नलिखित चार प्रमुख प्रदेयों (Deliverables) पर सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने में सफल रहा- - भविष्य के शहरों के वित्त-पोषण पर G-20 सिद्धांत; - भविष्य के शहरों के वित्त-पोषण पर G-20/ OECD रिपोर्ट; - शहरी प्रशासन के क्षमता निर्माण पर G-20/ ADB फ्रेमवर्क; तथा - समावेशी शहरों को सक्षम बनाने पर G-20/ विश्व बैंक रिपोर्ट।
अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें	- बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (HML): अब तक HML में 5 श्रेणियों के तहत 37 बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्र शामिल किए गए हैं। - श्री बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति अवसंरचना को परिभाषित करने वाली/ वाले विशेषताओं/ मापदंडों और अमृत काल के लिए वित्त-पोषण फ्रेमवर्क का व्यापक मूल्यांकन करेगी। - राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना दोनों क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ब्राउनफील्ड व ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। - NIP में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के अवसंरचना संबंधी 22 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं। - परिवहन (42%), ऊर्जा (25%), जल एवं स्वच्छता (15%) और सामाजिक अवसंरचना (3%) क्षेत्रक में किया गया निवेश, NIP के तहत किए गए कुल अनुमानित अवसंरचना निवेश का लगभग 85 प्रतिशत है।
अवसंरचना के वित्त-पोषण के लिए विनियामकीय सुधार	- SEBI ने InvITs के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट से जुड़े निर्देशों की एक श्रृंखला पेश करने हेतु InvIT विनियमों में संशोधन किया है। - RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (IDF-NBFCs) के लिए अपडेटेड दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF) योजना: स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में PPP मॉडल को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा VGF योजना के दायरे का विस्तार किया गया है। 2020 में इस योजना को एक नया रूप दिया गया था। इसमें VGF समर्थन में वृद्धि करते हुए इसे पूंजीगत व्यय (CAPEX) के लिए अधिकतम 80% तक और परिचालनगत व्यय (OPEX) के लिए अधिकतम 50% तक कर दिया गया है। VGF समर्थन का स्तर अलग-अलग क्षेत्रक से संबंधित PPP परियोजनाओं और उनकी ,रूपरेखा के आधार पर अलग-अलग होता है।

	• भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF) का पुनरुद्धार: इसे 03.11.2022 को एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह PPP परियोजना की तैयारी के लिए PPP परियोजना से संबंधित प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। ◦ IIPDF को एक रिवाल्विंग फंड के रूप में गठित किया गया था। इसे रिफंडेबल ऋण के रूप में वितरित किया जाता था। • लेन-देन से जुड़े सलाहकारों (Transaction Advisors) का पैनल बनाना: गुणवत्तापूर्ण PPP परियोजना संरचनाओं की शुरुआत करने के लिए लेन-देन से जुड़े 12 सलाहकारों को एक पैनल में शामिल किया गया है। • नीतिगत उपाय और दस्तावेज़: राज्य PPP इकाइयों की स्थापना के लिए रेफरेंस गाइड; PPP परियोजना मूल्यांकन के लिए रेफरेंस गाइड; प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मोड सिलेक्शन-वॉटरफॉल फ्रेमवर्क के लिए रेफरेंस गाइड आदि।
वित्तीय क्षेत्रक में सुधार	• NSE IFSC-SGX कनेक्ट (द कनेक्ट) 29 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया गया था। यह 03 जुलाई, 2023 से पूरी तरह से चालू हो गया है। अब SGX निफ्टी डेरिवेटिव्स का विशेष रूप से NSE IFSC पर कारोबार होता है। ◦ इस परिवर्तन के बाद, सभी अमेरिकी डॉलर-मूल्य वाले निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार विशेष रूप से NSE IFSC पर किया जाता है। • विदेशी संस्थानों की शाखाओं/परिसरों की स्थापना के लिए सक्षम नियम अधिसूचित किए गए हैं। ◦ ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी और वॉलॉन्गॉन्ग यूनिवर्सिटी, गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा परिसर स्थापित करेंगे। इस स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाले ये पहले दो विदेशी विश्वविद्यालय बन गए हैं। • T+1 सेटलमेंट: T+1 सेटलमेंट साइकल में परिवर्तन जनवरी 2023 में पूरा हो गया था। इसे नवंबर 2021 में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया था।

7. लोक उद्यम विभाग (वित्त मंत्रालय) {Department of Public Enterprises (Ministry of Finance)}

CPSEs के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए MoU डैशबोर्ड	• 2021-22 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) के साथ MoU की वार्षिक प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें CPSEs से डेटा संग्रह करना, प्रशासनिक मंत्रियों द्वारा इसका सत्यापन करना तथा MoU पर हस्ताक्षर और उनका मूल्यांकन करना शामिल हैं। • CPSEs के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए MoU हेतु बनाए गए ऑनलाइन डैशबोर्ड ने 2022 में 'ई-गवर्नेंस' श्रेणी में 'स्कोच (SKOCH) गोल्ड अवार्ड' प्रदान किया है।
CPSEs द्वारा खरीद	• गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से CPSEs द्वारा की गई खरीद साल-दर-साल आधार पर लगभग 2.7 गुना बढ़ी है। • 30 नवंबर, 2023 तक सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSEs) से खरीद निर्धारित लक्ष्य से 10% अधिक रही है।

8. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) {Department of School Education & Literacy (Ministry of Education)}

मुख्य तथ्य	समग्र शिक्षा योजना: सरकार ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना को पांच साल की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। विद्या प्रवेश: 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने कक्षा 1 के छात्रों के लिए विद्या प्रवेश नामक 3 महीने का खेल-आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' लागू किया है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA/निष्ठा) का विस्तार किया गया है। इसके तहत मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों को भी कवर किया जाएगा। प्रधान मंत्री पोषण योजना को जारी रखना: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2021-22 से 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। - सभी जिलों में पीएम पोषण योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोगो, स्लोगन/ टैगलाइन: 'जन जनसाक्षर' नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का स्लोगन है तथा ULLAS अर्थात 'अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी' नया नाम है। जादुई पिटारा: NEP 2020 की सिफारिशों के बाद, जादुई पिटारा शिक्षण सामग्री तथा कक्षा I और II के लिए पाठ्यपुस्तकें लॉन्च की गई हैं। समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तथा कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (NGIFEIE) को अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही, इसके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों को दी गई है। विद्यांजलि: इस कार्यक्रम में 2023 के दौरान, 6,84,147 स्कूल शामिल हुए थे। 4,46,898 स्वयंसेवकों ने विद्यांजलि पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। विद्यांजलि: यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह स्वयंसेवकों को सीधे स्कूलों से जोड़कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।
नई पहलें	परख/ PARAKH: NCERT ने एक स्वतंत्र घटक निकाय के रूप में परख की स्थापना की अधिसूचना जारी की थी। इसका उद्देश्य सभी स्कूल परीक्षा बोर्डों को एक मंच पर लाने के लिए संस्थागत संरचनाएं और गठजोड़ बनाना है। परख/ PARAKH: समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। - इस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क: NCF-SE के तहत पाठ्यक्रम को NEP, 2020 के साथ जोड़ा गया है। इसमें स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 डिजाइन पर जोर दिया गया है। अपने नेताओं को जानें कार्यक्रम: इस पहल की शुरुआत 02 अक्टूबर, 2023 को संसद भवन में की गई थी। उम्मीद (समझना, प्रेरित करना, प्रबंधित करना, सहानुभूति रखना, सशक्त बनाना, विकसित करना) दिशा-निर्देश: NCERT ने CBSE, KVS और NVS के परामर्श से छात्रों/ स्कूल जाने वाले बच्चों में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

9. संसदीय मामलों का मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs)

विधायी कार्य	संसद के विधायी कार्य	लोक सभा	राज्य सभा	कुल
	प्रस्तुत किए गए विधेयक	41	05	46
	पारित किए गए विधेयक	47	49	
	दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक			49*

संसद का विशेष सत्र	- इसकी शुरुआत 18 सितंबर, 2023 में पुराने संसद भवन में की गई थी। - इसके बाद दोनों सदनों ने अपनी कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू की, जिसे 'संसद भवन' (SANSAD BHAVAN) नाम दिया गया है। - सेंट्रल हॉल सहित पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' का नाम दिया गया है। - इस दौरान "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" अर्थात "संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023" पारित किया गया था।
शून्यकाल	संसद के विशेष सत्र के दौरान लोक सभा में 333 मामले और राज्य सभा में 204 मामले उठाए गए थे।
युवा संसद	- अन्य संबंधित योजनाओं के तहत केंद्रीय विद्यालयों (KVs), जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs), दिल्ली के स्कूलों और विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। - राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। - जनवरी 2022 से अगस्त 2023 के दौरान हर महीने कम-से-कम एक संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठकें आयोजित की गई थीं।
सलाहकार समितियां	- संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सांसदों की सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। साथ ही, यह सत्र और दो सत्रों की अवधि के दौरान उनकी बैठकें भी आयोजित करने की व्यवस्था करता है। 17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के लिए कुल 37 सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।
आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)	2023 में कुल 395 कार्यान्वयन रिपोर्ट लोक सभा में और कुल 303 कार्यान्वयन रिपोर्ट राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थीं।
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)	वर्तमान में, 22 विधान-मंडलों ने संसदीय मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 18 विधान-मंडलों को परियोजना संबंधी मंजूरी और वित्त-पोषण प्राप्त हुआ है।

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region: MDoNER)

MDoNER/ पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की योजनाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश	- दो घटकों के साथ पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) को जारी रखना। इन दो घटकों में 'NESIDS-सड़क' और 'NESIDS-सड़क के अतिरिक्त अवसंरचनाएं' (OTRI) शामिल हैं। - NESIDS 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 'NEC की योजनाओं' को जारी रखना। 21 अगस्त, 2023 को पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
सरकारी योजनाएं	- पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE) 26 दिसंबर, 2023 तक 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मंजूरी प्रदान करने हेतु 14 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

	○ इसके अलावा, PM-DevINE के तहत सैद्धांतिक रूप से 12 चयनित परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। • पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (सड़क) {NESIDS (Roads)} ○ अब तक, 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 3 परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए चुना गया है। ○ इसके अलावा, NESIDS (Roads) के तहत 21 परियोजनाओं के चयन की सिफारिश की गई है। • पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (सड़क अवसंरचना के अतिरिक्त)-NESIDS (OTRI) ○ इसके तहत कुल 1548 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें से 1098 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 450 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। • पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की योजनाएं ○ भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की योजनाएं NER के त्वरित और समग्र विकास के लिए कई क्षेत्रों में 'क्रिटिकल गैप इंटरवेंशन' के साथ जारी रहीं। ○ अब तक, NEC की योजनाओं के तहत 195 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। • विशेष विकास पैकेज ○ बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC): गृह मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत, तीन वर्षों के लिए ₹750 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ○ कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (KAATC): नए KAATC पैकेज के तहत KAATC क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ○ दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (DHATC): 200 करोड़ रुपये के पुराने DHATC पैकेज के तहत 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 13 परियोजनाएं चल रही हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता के तहत व्यय	• सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, सभी गैर-ब्लूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों (वर्तमान में 54) हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि वे केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अपने सकल बजटीय समर्थन (GBS) का कम-से-कम 10 प्रतिशत खर्च करेंगे।
अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं	• अगरतला-अखौरा रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन। • MDoNER ने AMTRON के सहयोग से NER राज्यों में 5G एप्लिकेशन लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। • पूर्वोत्तर निवेश प्रोत्साहन: इस उद्देश्य के लिए चिन्हित फोकस के क्षेत्रों में शामिल हैं: ○ कृषि और संबद्ध क्षेत्र, हस्तशिल्प तथा हथकरघा, पर्यटन और आतिथ्य, आई.टी. & आई.टी.ई.एस., खेल और मनोरंजन, शिक्षा और कौशल विकास और स्वास्थ्य देखभाल।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (North Eastern Handicrafts & Handlooms Development Corporation Limited : NEHHDC)	- गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र। - इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, मुशालपुर, बक्सा (असम) में एक ERI रेशम कताई संयंत्र की स्थापना।
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (NERAMAC)	- कृषि-बागवानी उपज की खरीद: अपने प्रमुख ब्रांड 'एनई फ्रेश (NE Fresh)' के तहत अनानास, एवोकाडो, ब्लैक राइस, काजू जैसी उपज की खरीद। - जी.आई. टैग प्राप्त उत्पादों के विपणन के लिए 'नेरामैक प्रीमियम' नामक ब्रांड लॉन्च किया गया। - पूरे NER में 15,500 किसानों को शामिल करते हुए 205 FPOs का गठन किया गया है। - सभी 13 जी.आई. पंजीकृत कृषि-बागवानी उत्पादों के लिए NER के 1308 किसानों को उपयोगकर्ता प्राधिकरण पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है।
पूर्वोत्तर बेंत एवं बांस विकास परिषद (NECBDC)	- असम और मणिपुर के NECBDC क्लस्टर के कारीगरों को 115 व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा किट वितरित की गई। 463 से अधिक लोगों को बेंत और बांस से संबंधित उत्पादों के बारे में प्रशिक्षित किया गया।
अन्य उपाय	- MDoNER डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड में 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा है। - यह MDoNER को डेटा के आधार पर निर्णय लेने, संचालन को सुगम बनाने, केंद्रीकृत निगरानी, नीति के स्तर पर निर्णय लेने और सूचना एकीकरण में मदद करेगा। - बेहतर स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: - पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के उद्यमशीलता परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है जिसमें 4500 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और 25 सक्रिय इनक्यूबेटर्स शामिल हैं। - स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार, असम और अरुणाचल प्रदेश को अग्रणी स्थान दिया गया है। मेघालय राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है। मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा को महत्वाकांक्षी अग्रणी और मिजोरम को उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम का दर्जा दिया गया है। - पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए अक्टूबर 2023 में एक कार्य बल का गठन किया गया। इसमें संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। - कृषि के लिए अंतर-मंत्रालयी कार्य बल ने अपनी सिफारिशें दी हैं। - MoA&FW बांस से संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन पर काम करेगा; RKVY के तहत NER के लिए अधिक परिव्यय, क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती, अगरवुड को बढ़ावा देने आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

	• नॉर्थ ईस्ट पोर्टल को आगे बढ़ाना: यह NEC द्वारा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (NEDFi) के जरिए विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेब-आधारित पहल है, जो पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। • आजीविका सृजन के लिए डिज़ाइन लैब्स: परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करके उन्हें ज्ञान अर्थव्यवस्था/ डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाना है।
--	---

11. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प	• वर्तमान में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता लगभग 426 गीगावाट है। • वित्त वर्ष 2023-24 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 9,943 मेगावाट जोड़ा गया, जिनमें से 8,269 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। • वित्त वर्ष 2023-24 में जोड़ी गई नवीकरणीय ऊर्जा (बड़ी पनबिजली परियोजना सहित) की 7569 मेगावाट क्षमता में शामिल हैं: ○ सौर ऊर्जा- 5,531 मेगावाट, ○ पवन ऊर्जा- 1,931 मेगावाट, ○ बायोमास ऊर्जा- 34 मेगावाट, ○ लघु पनबिजली ऊर्जा- 42 मेगावाट, और ○ वृहद पनबिजली ऊर्जा- 30 मेगावाट। • हर गांव और हर घर तक विद्युत/ बिजली पहुंचा दी गई है। • 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता प्रतिदिन 12 घंटे से बढ़कर 20.6 घंटे हो गई है और शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 23.8 घंटे हो गई है। • 2022-23 की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान नवीकरणीय स्रोतों सहित कुल विद्युत उत्पादन में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। • पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान ऊर्जा आवश्यकता में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। • पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पीक डिमांड में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत/ पनबिजली परियोजनाएं	• NHPC⁴ लिमिटेड, NEEPCO⁵ लिमिटेड और SJVN⁶ लिमिटेड ने राज्य में 12 लंबित जल विद्युत परियोजनाओं (स्थापित क्षमता 11,523 मेगावाट) के विकास के लिए अगस्त 2023 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
समर्थ मिशन	• जून 2023 में संशोधित बायोमास नीति जारी की गई। इसमें बायोमास पैलेट्स की बेंचमार्किंग कीमत और पैलेट्स की खरीद प्रक्रिया को दर्शाया गया है। • बायोमास खरीद के लिए संशोधित मॉडल अनुबंध जारी किया गया है। • SBI के सहयोग से पैलेट-ब्रिकेट निर्माण के लिए बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट जारी की गई है।

⁴ National Hydroelectric Power Corporation/ राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

⁵ North Eastern Electric Power Corporation

⁶ Satluj Jal Vidyut Nigam

	- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)⁷ के माध्यम से बायोमास पैलेट संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने की सुविधा का प्रावधान किया गया है। - वर्ष 2023 में कुल बायोमास का उपयोग 2.08 LMT (लाख मीट्रिक टन) से अधिक हो गया है।
ट्रांसमिशन क्षमता में वृद्धि	2023 के दौरान, 14,390 ckm ट्रांसमिशन लाइनें, 61,591 MVA ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और 4,290 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को जोड़ा गया है।
2030 तक 500 गीगावाट से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन योजना	- भारत ने ऊर्जा ट्रांजिसन की दिशा में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके तहत 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 क्षमता की बिजली स्थापित क्षमता हासिल करने की योजना है। - केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने "2030 तक 500 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" शीर्षक से एक विस्तृत योजना तैयार की है। 30 नवंबर, 2023 तक चालू की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता 179.6 गीगावाट है। - इसके अलावा, 64.1 गीगावाट क्षमता की पवन और सौर ऊर्जा के एकीकरण के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) नेटवर्क निर्माणाधीन है तथा 63.8 गीगावाट पवन और सौर क्षमता के लिए, ISTS नेटवर्क बोली प्रक्रिया के अधीन है। - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC- I&II) योजना के तहत, लगभग 26.1 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को इंटर-स्टेट नेटवर्क में एकीकृत किए जाने की संभावना है।
पुनर्निर्माण वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme: RDSS)	- यह योजना DISCOMs को उनकी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। - इस योजना के तहत संबंधित एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ फीडर और डिजिटल (DT) स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग लागू की जाएगी। - योजना के तहत किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) घाटा कम होकर 15.41% (अनंतिम) हो गया है।
राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	- स्मार्ट वितरण शहरों के लिए मूल्यांकन का नेतृत्व करना। "एंड कंज्यूमर एप्लीकेशन्स के साथ एनर्जी डेटा साझा करने के मानकीकृत तरीके" के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की गई है।
सरकारी योजनाएं	- सभी के लिए किफायती एल.ई.डी. द्वारा उन्नत ज्योति (UJALA)⁸ योजना। - इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 48.39 बिलियन किलोवाट घंटे की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है। साथ ही, प्रति वर्ष 39.30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के समतुल्य GHG उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अलावा, उपभोक्ता बिजली बिलों में 19,332 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक मौद्रिक बचत भी हुई है।

⁷ National Single Window System

⁸ Unnat Jyoti by Affordable LEDs for ALL

	• स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP) ○ अब तक, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) ने पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और ग्राम पंचायतों में 1.30 करोड़ से अधिक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। ○ इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 6.03 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बराबर GHG के उत्सर्जन में कमी आई है।
बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार	• बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन किया गया है। इसमें टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ की शुरुआत करके नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की अधिक से अधिक खपत की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। • सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ जीवनयापन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग नियमों को भी सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। ○ स्मार्ट मीटर को दिन में कम से कम एक बार दूर से पढ़ा जाएगा और डेटा को उपभोक्ताओं के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे बिजली की खपत के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।
विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 में संशोधन	• संशोधित नियमों के तहत ओपन एक्सेस सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दिया है। इससे कम ऊर्जा उपभोग करने वालों के लिए भी नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान के लिए वैधानिक तंत्र	• इसमें बकाया के भुगतान के लिए एकमुश्त योजना का प्रावधान किया गया है। इससे डिस्कॉम को अधिसूचना की तारीख तक विलंब भुगतान अधिभार (LPS)⁹ सहित कुल बकाया राशि का भुगतान 48 मासिक किस्तों में करने में मदद मिलेगी।

12. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय {Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)}

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	• ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विनियम संहिता और मानकों के फ्रेमवर्क बनाने के लिए MNRE सचिव की अध्यक्षता वाले कार्य-समूह ने सिफारिशों के पहले सेट को साझा किया। • ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT)¹⁰ कार्यक्रम की घोषणा की गई। • MNRE ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के सहयोग से जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। • अगस्त 2023 में भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया गया। • अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोडमैप जारी किया गया।
--------------------------------	--

⁹ Late Payment Surcharge

¹⁰ Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition

	अक्टूबर 2023 में 'भारत सरकार के राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (NSWS)' पर ग्रीन हाइड्रोजन पेज शुरू किया गया।
हरित ऊर्जा गलियारा	MNRE ने लद्दाख में 12000 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के साथ-साथ 13,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की योजना भी बनाई है।
अपतटीय पवन ऊर्जा	- सितंबर 2023 में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक संशोधित रणनीति जारी की गई। - डेवलपर्स को अपतटीय पवन समुद्री ब्लॉक्स के आवंटन को विनियमित करने के लिए दिसंबर 2023 में "अपतटीय पवन ऊर्जा लीज नियम, 2023" अधिसूचित किया गया।
सौर ऊर्जा	- उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना - किश्त-II के तहत, 39,600 मेगावाट पूर्ण/ आंशिक रूप से एकीकृत सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए अप्रैल 2023 में लेटर्स ऑफ अवार्ड जारी किया गया। - सौर पार्क 30 नवंबर, 2023 तक मंत्रालय ने देश भर में 12 राज्यों में लगभग 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी। - पीएम कुसुम - पीएम कुसुम योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। अब घटक B और C के तहत 49 लाख पंपों की स्थापना/ सोलरीकृत करने का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया। - रूफटॉप सोलर - जनवरी से नवंबर 2023 के दौरान ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम के तहत लगभग 741 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई।
जैव-ऊर्जा	- बायोमास न जलाने और इसे बायोएनर्जी उत्पादन में उपयोग करने हेतु संदेश फैलाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में अभियान चलाया गया। - वर्ष के दौरान 105 MWeq की बायोएनर्जी परियोजना (बायोमास तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं) क्षमता स्थापित की गई।
नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO)	- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत मार्च 2030 तक नामित उपभोक्ताओं के लिए RPO के लक्ष्यों को अधिसूचित किया। 'वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE)' के लिए अलग RPO जारी किया गया।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency: IREDA)	- RBI ने IREDA को 'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC)' का दर्जा दिया। - निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने IREDA के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए वैकल्पिक तंत्र की मंजूरी की सूचना दी। - IREDA को 'अनुसूची B' से 'अनुसूची A' श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (CPSE) में अपग्रेड कर दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी प्रेसीडेंसी	भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के 13वें सत्र (असेंबली) की अध्यक्षता ग्रहण की।
G20 एनर्जी ट्रांजिशन कार्य-समूह तथा एनर्जी ट्रांजिशन मंत्रिस्तरीय बैठक (ETMM)	- एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की चार बैठकें आयोजित की गईं। - ETMM में, G20 ऊर्जा मंत्रियों ने एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी आउटकम डॉक्यूमेंट और चेयरस समरी (Chair's Summary) को अपनाया।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)	- अक्टूबर 2023 में ISA असेंबली का छठा सत्र भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित किया गया। - सत्र के दौरान 5 से अधिक सदस्य देशों ने स्वैच्छिक योगदान की पुष्टि की। यह इस सत्र का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा।

13. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)

पी.एम. विश्वकर्मा योजना	यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ बाजार पहुंच में सुधार करना है।
अन्य योजनाएं/ पहलें	ऋण तक पहुंच (Access to Credit) - प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2023 में संशोधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी (CGTMSE) योजना शुरू की गई। इसके तहत गारंटी कवरेज की सीमा को बढ़ाया गया, गारंटी शुल्क को कम किया गया, और कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए ग्रेडहोल्ड सीमा को बढ़ा दिया गया। - आत्मनिर्भर भारत (SRI) कोष: NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (NVCFL) के साथ 14 सहायक फंड्स (डॉटर्स फंड) को सूचीबद्ध किया गया। - SRI फंड का उद्देश्य MSME क्षेत्रक के पात्र और उपयुक्त इकाइयों को विकास पूंजी (ग्रोथ कैपिटल) प्रदान करना है। अवसररचना एवं क्षमता निर्माण - सूक्ष्म एवं लघु-उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP), - पारंपरिक उद्योगों के पुनर्निर्माण हेतु निधि योजना (SFURTI)¹¹: जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 89 क्लस्टरों ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे 25 राज्यों में 50,166 कारीगरों को लाभ पहुंचा है। 'नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना' (ASPIRE)¹²: इसका उद्देश्य कृषि-ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके 2 घटक हैं: - लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर (LBIs)¹³: 2023 में एस्पायर के तहत 4 नए LBIs को मंजूरी दी गई। - एस्पायर फंड ऑफ फंड्स (FoF): इसके तहत 5 नए वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) को समर्थन दिया गया।

¹¹ Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries

¹² A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship

¹³ Livelihood Business Incubator

खरीद एवं विपणन सहायता	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति - सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा MSE से 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद करना अनिवार्य किया गया है। इसमें निम्नलिखित शर्तें भी हैं: - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले MSE से 4 प्रतिशत खरीद, और - महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSE से 3 प्रतिशत खरीद। - खरीद और विपणन सहायता (PMS) योजना: 2023 तक, MSME मंत्रालय ने 253 व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिससे लगभग 9,500 MSEs लाभान्वित हुए हैं।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (India International Trade Fair: IITF), 2023	नवंबर 2023 में आयोजित 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2023 में "पीएम विश्वकर्मा" थीम के साथ "MSME पवेलियन" का उद्घाटन किया गया।
निर्यात प्रोत्साहन	MSME मंत्रालय ने 59 निर्यात सुविधा सेल (EFCs) की स्थापना करके MSME क्षेत्र से निर्यात प्रोत्साहन के लिए समर्पित सहायता प्रणाली विकसित किया है।
प्रौद्योगिकी तक पहुंच	- MSME चैंपियंस - इस योजना के तीन घटक हैं - 'MSME-सस्टेनेबल' (ZED), 'MSME-प्रतिस्पर्धी' (LEAN) और 'MSME-इनोवेटिव' (इनक्यूबेशन, डिजाइन, IPR)। - मार्च 2023 में MSME प्रतिस्पर्धी (LEAN) योजना शुरू की गई। - प्रौद्योगिकी केंद्र: इसे टूल रूम और तकनीकी संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। - भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (CTTC) ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' के लिए 437 प्रकार के सटीक पुर्जों का निर्माण करके इनकी आपूर्ति की। - CTTC भुवनेश्वर ने भारत का पहला सौर मिशन 'आदित्य L1' के लिए रेगुलेटर, फ्लो कंट्रोल वाल्व, जायरोस्कोप, टेम्परेचर सेंसर और नेविगेशन उपकरणों जैसे सटीक पुर्जों का निर्माण करके मिशन में अपना योगदान दिया।
कौशल विकास	2023 में उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) के तहत 1,579 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में MSMEs को बढ़ावा देना	- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) - इसका उद्देश्य SC/ ST समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत CPSEs द्वारा ऐसे उद्यमियों से 4% खरीद की अनिवार्यता को पूरा करना। - वर्ष 2023 के दौरान, SC/ ST बहुल क्षेत्रों में 6 बड़े कार्यक्रम (NSSH कॉन्क्लेव) आयोजित किए गए। "पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) और सिक्किम में MSMEs को प्रोत्साहन" योजना - इस योजना के तहत, औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 4 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें मिजोरम की 2 तथा त्रिपुरा और असम की 1-1 परियोजना शामिल हैं।

	○ इस योजना के दो घटक हैं: ▪ नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र का आधुनिकीकरण; नए एवं मौजूदा औद्योगिक एस्टेट का विकास, तथा ▪ पर्यटन क्षेत्रों का विकास।
रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम (RAMP) योजना	• RAMP के तहत तीन उप-योजनाएं शुरू की गई हैं: ○ MSE-GIFT (MSE हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण¹⁴), ○ MSE-SPICE (सर्कुलर इकोनॉमी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए MSE योजना¹⁵), तथा ○ विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना। • MSME में महिला उद्यमियों के लिए ZED प्रमाणन नि:शुल्क कर दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा जूट उत्पाद विकास और निर्यात संवर्धन परिषद (JPDEPC) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। • भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी रोडमैप (IJICP) के तहत गठित “MSME सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (JWG)” की दूसरी बैठक आयोजित की गई। • इंडिया SME फोरम के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 का आयोजन किया गया। • 12वीं “मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM)” बैंकॉक में आयोजित की गई। इसमें सहयोग को बढ़ावा देने वाले तंत्र के तहत 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में MSME को शामिल किया गया।
खादी, ग्रामोद्योग और नारियल-कॉयर (Coir) क्षेत्रों को बढ़ावा देना	• खादी एवं ग्रामोद्योग ○ खादी संस्थानों की मौजूदा कमजोर अवसंरचना को मजबूत करने और विपणन के लिए सहायता पहल के तहत, 40 खादी संस्थानों (KIs) को मजबूत किया गया। साथ ही, 65 सेल्स आउटलेट्स को नवीनीकृत किया गया। • ग्रामोद्योग विकास योजना (ग्रामोद्योग कार्यक्रम) ○ खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम के तहत 1,862 इलेक्ट्रिक पाँटर व्हील वितरित किए गए। ○ कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अन्तर्गत शहद मिशन/ मधुमक्खी पालन के तहत 15,310 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए हैं।
NSIC और MGIRI की उपलब्धियां	• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) ○ NSIC कच्चे माल की खरीद हेतु बैंक गारंटी के लिए “कच्चे माल सहायता योजना” के तहत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके ऋण सहायता प्रदान करता है। • महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (MGIRI) ○ 2023 के दौरान, MGIRI ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही, KVIC जैसे कार्यक्रमों और संगठनों के लिए उचित तालमेल स्थापित किया गया।

¹⁴ MSE Green Investment and Financing for Transformation

¹⁵ MSE Scheme for Promotion of Investment in Circular Economy

शिकायत निवारण पोर्टल	'अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस', 2023 के अवसर पर चैंपियंस 2.0 की शुरुआत की गई। इस पोर्टल को यूजर-फ्रेंडली बनाने तथा शिकायतों का कम समय में समाधान करने के लिए अपग्रेड किया गया है।
----------------------	---

14. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)}

प्रमुख पहलें और उपलब्धियां	16वां सिविल सेवा दिवस "विकसित भारत – एंपावरिंग सिटीजंस एंड रिचिंग दी लास्ट माइल" थीम पर आयोजित किया गया। - तृतीय सुशासन सप्ताह, 2023 का आयोजन किया गया।
लोक शिकायतों का प्रभावी निवारण	2023 में CPGRAMS पोर्टल में प्रौद्योगिकी संबंधी सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं: - CPGRAMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, - इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और ट्री-डैशबोर्ड का शुभारंभ, तथा - CPGRAMS पोर्टल के साथ AI आधारित भाषिणी का एकीकरण।
ई-ऑफिस एनालिटिक्स कार्यान्वयन	- कुल फाइल्स में से ई-फाइल्स में रूपांतरण के स्तर पर ई-ऑफिस को 90 प्रतिशत अपनाया गया। - कुल रिसीट्स में से 90% ई-रिसीट्स सृजित करके डिजिटलीकरण किया गया। - ई-ऑफिस फ़ाइल मूवमेंट के तहत निर्णय लेने के अलग-अलग लेयर को कम करने के प्रयास के तहत वर्ष 2020 में 8.01 लेयर से घटाकर नवंबर 2023 में 4.11 लेयर कर दिया गया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।
अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग	- भारत और फ्रांस के बीच 3 वर्षों की अवधि के लिए लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों में सहयोग पर आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए गए। - इसके अलावा, सिंगापुर के लोक सेवा प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया।
राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA), 2023	- NeSDA, 2021 की सिफारिशों को समय पर लागू करने के लिए "NeSDA- वे फॉरवर्ड, स्टेटस ऑफ़ इम्प्लीमेंटेशन" डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। - नवंबर 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा नागरिकों को 16000 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। - अनिवार्य ई-सेवाओं की पहुंच NeSDA, 2019 के 48 प्रतिशत से बढ़कर NeSDA, 2023 में 78 प्रतिशत तक हो गई।
अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2023 के दौरान, NCGG ने 28 अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
अन्य पहलें	- राज्य सहयोगात्मक पहल योजनाएं: ई-ऑफिस समाधान, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक शिकायतों के डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा का समाधान आदि विषयों पर अलग-अलग राज्यों के साथ 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। - अभिनव पहल ई-सीरीज: प्रधान मंत्री पुरस्कारों के तहत सम्मानित पहलों की सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार करने के लिए संसद टीवी पर अभिनव पहल ई-सीरीज कार्यक्रम शुरू किया गया। - जिला सुशासन सूचकांक (DGGI): यह सूचकांक जिला स्तर पर गवर्नेंस की बेंचमार्किंग से संबंधित अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है।

15. पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Department of Pension & Pensioners' Welfare (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions)}

पेंशन प्राप्ति आसान करना	- विभाग ने पेंशनरों की पुरानी शिकायतों के निवारण के लिए अखिल भारतीय पेंशन अदालतों का आयोजन किया। - इसके अलावा, पेंशनभोगियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 'भविष्य' नामक एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च किया गया। - राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। यह पेंशनभोगियों को एंड्रॉइड स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। - नवीनतम पेंशन नियम/ प्रक्रिया और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बैंकर्स अवेयरनेस वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया।
--------------------------	---

16. केंद्रीय सूचना आयोग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) {Central Information Commission (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions)}

मुख्य उपलब्धियां	- केंद्रीय सूचना आयोग ने 1 जनवरी से 13 दिसंबर के बीच 19,207 शिकायतें दर्ज की थीं। त्वरित कार्यवाही करते हुए आयोग ने इनमें से 18,261 शिकायतों का निपटारा कर दिया है। - वर्ष 2023 के लिए 20 सार्वजनिक प्राधिकरणों का सैंपल ट्रांसपेरेंसी ऑडिट आयोजित किया गया।
------------------	---

17. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

प्रमुख उपलब्धियां	स्वामित्व/ SVAMITVA योजना: दिसंबर 2023 तक 1.06 लाख गांवों के लिए लगभग 1.63 करोड़ स्वामित्व कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। - इस योजना को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के तत्वाधान में आयोजित 'नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग' में स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। - इसे डिजिटल कॉन्क्लेव 2023 में डिजिटल रूपांतरण हेतु 'ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग' के लिए गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: इसके तहत 28 दिसंबर, 2023 तक 17 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। - इस योजना को 2022-23 और 2025-26 की अवधि में जारी रखने हेतु संशोधित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (LSDGs) करने के लिए प्रयास किए गए। जन योजना अभियान (PPC)-2023: इसकी शुरुआत 04 सितंबर, 2023 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में शुरू किया गया। इसे 'अभियान मोड' में सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने की रणनीति के रूप में आरंभ किया गया। पंचायत विकास सूचकांक (PDI): LSDGs में हुई प्रगति को मापने और तथ्यों के आधार पर नीति-निर्माण हेतु मूल्यांकन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
-------------------	---

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाने के लिए संस्थागत तंत्र	- PRIs को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के विषयों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पंचायती राज (SoEPR) की स्थापना की गई। - पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगस्त 2023 में मेरी पंचायत एप्लिकेशन लॉन्च की गई। - प्रशिक्षणों के लिए मूल्यांकन मॉड्यूल को प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (TMP) में सक्रिय किया गया।
अन्य पहलें	- पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्रामस्वराज और GeM पोर्टल: इसका उद्देश्य ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, GeM के माध्यम से पंचायतों को वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की सुविधा प्रदान करना है। - mActionSoft: यह मोबाइल आधारित (ऐप) समाधान है। यह उन कार्यों के लिए जियो-टैग के साथ फोटो कैप्चर करने में मदद करता है, जिनमें आउटपुट के रूप में एसेट्स का निर्माण होता है।

18. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)

प्राथमिक सहकारी समितियों (PACS) की आर्थिक मजबूती के लिए पहलें	PACS/ पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उपनियम: इन उपनियमों का उद्देश्य PACS/ लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ (LAMPS) की आय के स्रोतों को बढ़ाना और डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण जैसे 25 से अधिक नए क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। प्रत्येक पंचायत/ गांव में बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना: अगले पांच वर्षों के भीतर अब तक कवर नहीं किए गए पंचायतों/ गांवों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। सहकारी क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत अनाज-भंडारण कार्यक्रम: इस कार्यक्रम की शुरुआत पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें जैसी कृषि अवसरचनाओं के निर्माण के लिए की गई है। ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए PACS को कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के रूप में मान्यता: बैंकिंग, बीमा जैसी कई ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को अधिकार: पेट्रोलियम मंत्रालय ने पैक्स को LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु पात्र बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। PACS द्वारा संचालित थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति: पेट्रोलियम मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी PACS को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जेनेरिक दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए PACS को जन औषधि केंद्र भी बनाया गया है। PACS को प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य करने की अनुमति: पहले से ही उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में कार्य कर रहे PACS को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। - PACS उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए "ड्रोन उद्यमी" के रूप में कार्य कर सकते हैं। - नाबार्ड की सहायता से बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-ATMs दिए जा रहे हैं। - सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जा रहे हैं। पानी समिति के रूप में "पैक्स": जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स को 'पानी समिति' के रूप में पात्र बनाने के लिए कहा है। मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO) का गठन: NCDC ने प्रारंभिक चरण में 69 FFPO का पंजीकरण किया है।
---	--

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023	इस अधिनियम के उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) में गवर्नेंस मजबूत करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना आदि।
राष्ट्रीय स्तर की तीन नई MSCS	- निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तरीय बहु-राज्य सहकारी समिति, - प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तरीय बहु-राज्य सहकारी समिति, - जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तरीय बहु-राज्य सहकारी समिति।
अन्य पहलें	- सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार में कमी: 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए आयकर पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। - सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कमी: सहकारी समितियों के लिए MAT दरें 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई। - PACS तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया। - नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती: नई सहकारी समितियों के लिए 30% तक की पिछली दर की तुलना में 15% की कम कर दर और अधिभार लिया जाएगा। - नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि: TDS के बिना सहकारी समितियों की नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। - सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी प्रदान की है। - सरकार ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी प्रदान की है। - भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSL): इसकी स्थापना देश के प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज उपलब्ध कराने के लिए की गई है।
सहकारी चीनी मिलों के लिए पहलें	- आयकर से संबंधित पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: सहकारी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले किए गए भुगतान को "व्यय" के रूप में दावा करने अनुमति दी गई। 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए NCDC को सहायता अनुदान': सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए नई योजना शुरू की गई है। यह पूंजी इथेनॉल संयंत्र या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए दी जाएगी। - इथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता: 'इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम' (Ethanol Blending Programme-EBP) के तहत इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के बराबर रखा जाएगा। - मोलासेस पर GST की दर को 28% से घटाकर 5% किया गया: इससे चीनी मिलों की तरलता (नकदी) बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सहकारी बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का निवारण	- सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई। - सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है। - भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) से जुड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। - सहकारी बैंकों को आधुनिक 'आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली' (AEPS) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी की गई है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पहले	- अनुसूचित दर्जा मानदंड: ऐसे UCBs जो "आर्थिक रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (FSWM)" मानदंडों को पूरा करते हैं और पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए रखते हैं, वे अब 'अनुसूचित' दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। - UCBs के लिए अम्ब्रेला संगठन: भारतीय रिज़र्व बैंक ने UCBs क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला संगठन (UO) के गठन के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी प्रदान कर दी है।
NCDC द्वारा सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई	- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार' योजना; - लंबी अवधि के कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; - डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' तथा महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' योजनाएं आदि। - NCDC डीप सी ट्रॉलर्स के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

19. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

प्रमुख उपलब्धियां	आदि महोत्सव: यह राष्ट्रीय मंच पर आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। साथ ही, यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक कार्यक्रम है। - यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) की एक वार्षिक पहल है। वन अधिकार अधिनियम: वन अधिकार अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर, 2023 तक कुल 1.8 करोड़ एकड़ से अधिक के 23.43 लाख भूमि स्वामित्व वितरित किए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRSs) के लिए 'अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम' का द्वितीय चरण: यह नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया है।
नई पहलें	प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (PVTGs) को 11 बुनियादी सुविधाएं देना सुनिश्चित करने के लिए 9-संबद्ध मंत्रालयों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर 100 जिलों में PM-JANMAN योजना का पहला चरण शुरू किया है। सिकल सेल उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन: इस मिशन का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 40 साल से कम उम्र के 8 करोड़ से अधिक आदिवासियों को सिकल सेल एनीमिया (SCA) की जांच करनी है। इनमें से 90 लाख लोगों के डेटा पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं।

20. अंतरिक्ष विभाग (Department of Space)

प्रमुख उपलब्धियां	चंद्रयान-3 मिशन: LVM3-M4 प्रक्षेपण यान ने 14 जुलाई, 2023 को चंद्रयान-3 को उसकी सटीक कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चंद्रयान-3 के लैंडर 'विक्रम' ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद रोवर "प्रज्ञान" चंद्रमा की सतह पर नेविगेट किया। - प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त (चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग तिथि) को "राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस" मनाने का निर्णय लिया गया। - चंद्रमा पर लैंडिंग स्थलों को शिव शक्ति पॉइंट (चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग) और तिरंगा पॉइंट (चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग) नाम दिया गया है। SSLV-D2/EOS-07 मिशन की दूसरी विकासात्मक उड़ान: SSLV "लॉन्च-ऑन-डिमांड" के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर सकता है।
-------------------	--

	• LVM3-M3/वनवेब मिशन: LVM3 M3/वनवेब इंडिया-2 मिशन इसका दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। इसने वनवेब कंपनी के 36 उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। • रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन (RLV LEX): इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR) में RLV LEX का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। • GSLV-F12/NVS-01 मिशन: इस मिशन को 29 मई, 2023 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। GSLV ने NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया। ◦ NVS-01 "नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC)" सेवा प्रदान करते हेतु दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। • गगनयान सर्विस मॉड्यूल हॉट टेस्ट: इसरो ने महेंद्रगिरि (तमिलनाडु) स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC) में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम (SMPS) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। • कू मॉड्यूल रिकवरी ट्रायल: इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कोच्चि में भारतीय नौसेना की "वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी (WSTF)" में कू मॉड्यूल की रिकवरी का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। • PSLV-C56/DS-SAR मिशन: DSTA (सिंगापुर सरकार) और ST इंजीनियरिंग के बीच एक साझेदारी के तहत DS-SAR उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। ◦ इस उपग्रह का उपयोग सिंगापुर सरकार की अलग-अलग एजेंसियों की सेटेलाइट इमेज संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। • आदित्य-L1 मिशन: यह भारत की पहली सौर वेधशाला है। इसे इसरो ने PSLV C57 से 2 सितंबर, 2023 को प्रक्षेपित किया। • गगनयान टेस्ट व्हीकल-D1: कू एस्केप सिस्टम (CES) के इन-फ्लाइट एबॉर्ट प्रदर्शन के साथ टेस्ट व्हीकल (TV-D1) की पहली विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई।
नई पहलें	• भारतीय अंतरिक्ष नीति- 2023: सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। • भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए: भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया। ◦ आर्टेमिस समझौता राष्ट्रों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग को निर्देशित करने के वाले सिद्धांतों का एक व्यावहारिक सेट स्थापित करता है।

21. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) {Department of Biotechnology (Ministry of Science & Technology)}

प्रमुख उपलब्धियां	• जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC): जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 14 स्वायत्त संस्थानों को BRIC में शामिल किया गया। • बायोटेक उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना: बायो-इनक्यूबेटर्स की संख्या 2014 में 6 थी, जो अब बढ़कर 75 से अधिक हो गई है। पिछले 9.5 वर्षों में देश में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 6,000 से अधिक हो गई हैं। • हीमोफीलिया A के इलाज के लिए भारत में पहला जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation) ने हीमोफीलिया A के इलाज लिए भारत के पहले जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी। • नोवेल ब्लड बैग रक्त बैग टेक्नोलॉजी का विकास: बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन (inStem), ने इलेक्ट्रोस्पून-नैनोफाइबर-शीट्स (Tau-AcrNFS) युक्त टॉरिन और एक्रिडीन विकसित किया है। यह मानव और चूहों की बाहर संग्रहित RBCs की क्षति को कम करता है। • ग्लोबल बायो इंडिया 2023: ग्लोबल बायो इंडिया 2023 इवेंट में बायोटेक स्टार्टअप्स द्वारा विकसित 29 नए उत्पाद लॉन्च किए गए।
-------------------	--

	• इंडिया बायो-इकोनॉमी रिपोर्ट 2023: इस रिपोर्ट को ग्लोबल बायो-इंडिया 2023 में लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bio-economy) ने पिछले 6-7 वर्षों से लगातार दोहरे अंक की CAGR से वृद्धि की है। • जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बीच समझौता ज्ञापन: इसका उद्देश्य DBT के बायो-डिजाइन केंद्रों पर चिकित्सा उपकरणों को डिजाइन करने और बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा पेशेवरों का समर्थन करना है। • दाल की फसलों के अंदर आयरन (Fe) और जिंक (Zn) का वैक्यूम अंतर्वेशन (Impregnation) सफलतापूर्वक पूरा किया गया: यह फाइटो को कम करता है और सजीवों में माइक्रोन्यूट्रिएंट जैव उपलब्धता में वृद्धि करने की क्षमता रखता है। • "सब्सट्रेट पर कोटिंग और तैयारी की प्रक्रिया के लिए बायो-फिल्म को रोकने वाली सोल-जेल संरचना" के लिए भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया। यह बायो-फिल्म अवरोधक सोल-जेल कोटिंग संरचना जीवाणुरोधी गुण प्रदान करती है। • कोयला से तरल प्रौद्योगिकी (Coal to Liquid technology: CTL): नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को CTL ऑयल में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया विकसित की गई है। इसमें अपशिष्ट परिवर्तन की दर 80% है। • राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत उपलब्धियां: ○ देश में चिकित्सीय उपकरणों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत, हल्का, अगली पीढ़ी के MRI स्कैनर का विकास किया गया है। ○ भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC)¹⁶: यह लाइफ-साइंसेज डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय रिपॉजिटरी है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान "जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (Regional centre of Biotechnology: RCB)" में स्थापित है। ○ टी.बी. उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान (Dare2eraD TB) पहल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mtb) के जैविक लक्षणों, तथा संचरण, उपचार एवं रोग की गंभीरता पर म्यूटेशन के प्रभाव को पूरी तरह से समझने वाली प्रथम "अखिल भारतीय पहल" है।
नई पहलें	• DBT IP दिशा-निर्देश 2023: ये दिशा-निर्देश DBT द्वारा वित्त पोषित बाह्य और आंतरिक दोनों संगठनों से बौद्धिक संपदा (IP) के हस्तांतरण को नियंत्रित करते हैं। • हार्ड परफॉरमेंस बायो-मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर नई पहल को शुरू किया गया है। • जैविक अनुसंधान विनियामक अनुमोदन पोर्टल (BioRRAP)¹⁷ का शुभारंभ: इसे बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए "एकल राष्ट्रीय पोर्टल" की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया गया है। • साइट डायरेक्टेड न्यूक्लीज-1 (SDN1) और SDN-2 श्रेणियों के तहत जीन एडिटिंग पौधों की विनियामक समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) अधिसूचित की गई हैं। • अदविका (ADVIKA)-सूखा-सहिष्णु और अधिक उपज देने वाली चने की किस्म: JG 16 की किस्म की जेनेटिक बैकग्राउंड में ABC ट्रांसपोर्टर जीन को प्रवेश कराकर यह किस्म विकसित किया गया है। यह सूखे की स्थिति में भी बीज के वजन और उपज को (7 % तक) बढ़ाता है। ○ इस सूखा-सहिष्णु चने की किस्म को अब "फसल मानकों पर केंद्रीय उप-समिति" ने मंजूरी दी है। • एक्सेल ब्रीड: फसल सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने "एक्सेलब्रीड" नाम से एक अत्याधुनिक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा विकसित की है।

¹⁶ Indian Biological Data Centre

¹⁷ Biological Research Regulatory Approval Portal

	वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए चावल प्रजनन में क्रांति हेतु IRRI का स्पीडफ्लावर प्रोटोकॉल: अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) ने वाराणसी में एक अत्याधुनिक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा स्थापित की है
टीके के विकास के लिए DBT's के प्रयास:	- सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (qHPV) टीका का विकास; - दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित टीका ZyCoV-D का विकास; - कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्रोटीन सब-यूनिट टीका CORBEVAX™ का विकास; - भारत का स्वदेशी रूप से विकसित mRNA वैक्सीन GEMCOVAC-19™; - भारत की पहली इंट्रानैसल कोविड-19 वैक्सीन INCOVACC का विकास; - mRNA प्लेटफॉर्म पर आधारित भारत का पहला ओमीक्रॉन बूस्टर वैक्सीन GEMCOVAC-OM का विकास।

22. परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)

प्रमुख उपलब्धियां	- काकरापार यूनिट-3 ने अपनी पूर्ण क्षमता से वाणिज्यिक रूप से विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है और काकरापार यूनिट-4 ने क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली है। - भारत का पहला फिशन मोलिब्डेनम-99 प्लांट (मुंबई) और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट, विशाखापत्तनम में शुरू हो गया है। - भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग से तैयार होने वाली फर्मिलैब परियोजना अपने निर्माण चरण में प्रवेश कर गई है। - LIGO इंडिया नामक एक “एडवांस गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला परियोजना” शुरू की गई। - स्कायर किलोमीटर एरे (SKA) में भारत की भागीदारी को मंजूरी दी गई। - MACE (मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोव एक्सपेरिमेंट) टेलीस्कोप ने रेडियो आकाशगंगा NGC 1275 से बहुत उच्च ऊर्जा वाले फोटॉनों का पता लगाया है। - विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार के लिए हाइब्रिड ग्रैनुलर सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर (hgSBR) विकसित किया गया। - किसानों के उत्पादों के प्रशीतित (Refrigerated) परिवहन के लिए शीतल वाहक यंत्र (शिवाय) विकसित किया गया है।
-------------------	--

23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science)

प्रमुख उपलब्धियां	- आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को शुरू किया गया। - गंभीर मौसम की पूर्वानुमान प्रणाली में 40-50% सुधार किया गया है। - वर्ष 2023 के दौरान चार डॉपलर मौसम रडार (Doppler Weather Radars: DWR) चालू किए गए। इससे देश में DWR की कुल संख्या 39 हो गई है। - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) को न्यूमेरिकल ओशन वेव पूर्वानुमान तथा वैश्विक न्यूमेरिकल ओशन पूर्वानुमान के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन-क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र (WMO- RSMC)¹⁸ के रूप में नामित किया गया। “हिंद महासागर जैव विविधता सूचना प्रणाली (IndOBIS)¹⁹” नामक वेब पोर्टल जनता के उपयोग लिए सार्वजनिक कर दिया गया। यह पोर्टल हिंद महासागर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की जैव विविधता को दर्शाता है।
-------------------	--

¹⁸ World Meteorological Organization-Regional Specialized Meteorological Centres

¹⁹ Indian Ocean Biodiversity Information System

	○ OBIS, “अंतर-सरकारी महासागर विज्ञान आयोग (IOC)- यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय महासागर विज्ञान डेटा और सूचना कार्यक्रम” के अंतर्गत शुरू की गई एक परियोजना है। • समुद्र (SAMUDRA) नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के बारे में सलाह सेवा देना; महासागर की स्थिति का पूर्वानुमान करना तथा सुनामी, चक्रवात, तूफानी लहरें, ऊंची लहरें, महोर्मि आदि पर अलर्ट जारी करना है। • भारत 2024-2027 की अवधि के लिए “विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)-उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर एशिया और प्रशांत पैनल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग सचिवालय” की मेजबानी की भूमिका निभाएगा। • लक्षद्वीप द्वीप समूह में खारे पानी को मीठा बनाने वाले 2 संयंत्रों (Desalination) का उद्घाटन किया गया।
--	---

24. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) {Council of Scientific and Industrial Research (Ministry of Science & Technology)}

प्रमुख उपलब्धियां	• हंसा-NG विमान (HANSA-NG Aircraft): CSIR-NAL ने हंसा-न्यू जनरेशन (NG) को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। यह उन्नत विशेषताओं से युक्त एक हल्का विमान है। • CSIR-CIMAP ने एक अनुसंधान में तंबाकू के पौधे में निकोटिन की मात्रा को कम करने में सफलता प्राप्त की है: जीनोम एडिटिंग टूल का उपयोग करके पेटिट हवाना नामक तंबाकू के पौधे की किस्म में निकोटिन की मात्रा को कम किया गया है। • Q-प्लेन और जलदोस्त (JALDOST) एयरबोट: Q-प्लेन वर्टिकल-टेक-ऑफ और लैंडिंग क्षमता से युक्त एक हल्का ऑल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड UAV है। ○ जलदोस्त एक एयरबोट है जो पानी पर चलती है और जल निकायों से अतिरिक्त जलीय खरपतवार तथा तैरते कचरे को हटाती है। • ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11: CSIR-CMERI ने इसे भारत के लघु और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। • नमो 108: CSIR-NBRI ने राष्ट्रीय पुष्प कमल की एक उन्नत किस्म 'नमो 108' (108 पंखुड़ियां) लॉन्च किया है। • लेवोर्मेलॉक्सिफ्रेन: भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने ओरल गर्भनिरोधक गोली 'लेवोर्मेलॉक्सिफ्रेन' के नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दे दी है। इसे CSIR-सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CDRI) और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। • CSIR की पहली बैटरी रीसाइक्लिंग पायलट सुविधा जमशेदपुर में शुरू की गई: इसे अपशिष्टों से लिथियम, निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण धातुओं को निकालने के लिए शुरू किया गया है। • कार्बन कंपोजिट फ्लैपरॉन टेस्ट बॉक्स: CSIR-NAL ने एक अत्याधुनिक फ्लैपरॉन स्ट्रक्चरल असेंबली को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है। इसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) के सहयोग से एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। • कई घटकों वाले एक नए मिश्र धातु-आधारित उत्प्रेरक को डिज़ाइन किया गया है, ताकि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन दक्षता के साथ किया जा सके। • AI की मदद से पानी के अंदर फिश कोरस सिम्फनी दर्ज की गई है: गोवा में अवस्थित CSIR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने पहली बार AI की मदद से समुद्री जीवन की मनोरम ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है।
-------------------	---

प्रमुख आयोजन	CSIR का 'वन वीक, वन लैब' अभियान: इसका उद्देश्य देश भर में स्थित CSIR 37 की प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की विविध विरासतों, विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित करना है। मिलेट्स पर CSIR द्वारा शोध कार्य: अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (2023) के अवसर पर CSIR द्वारा मिलेट्स पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। CSIR युवा पोर्टल: CSIR ने युवा स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोधकर्ताओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए युवा (Yuva Vaigyanik Anveshan: YUVA) पोर्टल लॉन्च किया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	भारत-मेक्सिको: भारत के CSIR और मेक्सिको के AMEXCID के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। भारत-इजराइल: CSIR और इजराइल के DDR&D के बीच बहु-क्षेत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

25. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर विनियमन	सेंट्रल प्रोसेसिंग फॉर एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (C-PACE): स्वैच्छिक रूप से व्यवसाय का परिचालन बंद करने का विकल्प चुनने वाली कंपनियों की सुविधा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। - आवेदनों की प्रोसेसिंग करने और उसे खारिज करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के जरिए C-PACE संचालित होता है। - C-PACE रजिस्ट्री पर दबाव को कम करता है और हितधारकों को अधिक सार्थक डेटा प्रदान करता है। स्ट्रेट श्रू प्रोसेस (STP) का उपयोग अतिरिक्त ई-फॉर्म के लिए किया जा रहा है। यह मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन और संचालन में तेजी लाता है। कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) के निगमन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2022 के 1,88,364 से बढ़कर वर्ष 2023 में 1,96,028 हो गया है। पंजीकृत कार्यालयों को स्थानांतरित करने हेतु प्रक्रियात्मक लागत को हटाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे कंपनियों का स्थानांतरण करना आसान हो गया है। लेखांकन प्रथाओं के बेहतर प्रकटीकरण से संबंधित भारतीय लेखा मानक IndAS 1, IndAS 8 और IndAS 12 में संशोधन किया गया है।
-------------------------------------	---

26. कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal)

प्रमुख उपलब्धियां	कोयले का उत्पादन: देश में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में हुआ है। कैलेंडर वर्ष 2023 (20 दिसंबर, 2023 तक) के दौरान, देश ने लगभग 918.62 मीट्रिक टन (अनंतिम आंकड़े) कोयले की आपूर्ति की है। पुनर्प्राप्त भूमि पर इको-पार्क और खदान पर्यटन का विकास करना: जनवरी-नवंबर 2023 के दौरान, कोयला/ लिग्नाइट PSUs ने 4 इको पार्क/ खदान पर्यटन स्थल विकसित किए हैं। परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण: कोयला मंत्रालय ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से नवंबर तक 48683 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। नीति आयोग ने इस वर्ष 50118 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कोयले का रेल-समुद्र-रेल द्वारा परिवहन: पिछले 4 वर्षों के दौरान कोयले के रेल-समुद्र-रेल द्वारा परिवहन में लगभग 125% की वृद्धि हुई है।
-------------------	---

सुधार/ नीतियां	- कोयला खान (विशेष प्रावधान) नियम, 2014 में संशोधन किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन जमा के रूप में बिड सिक्युरिटी को स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। - कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2023 ऑनलाइन डिपॉजिट के रूप में बिड सिक्युरिटी स्वीकार करने का प्रावधान करता है। - कोयला और लिग्नाइट खदानों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रबंधन ऑडिट पर दिशा-निर्देश: ये दिशा-निर्देश सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं।
2023 के दौरान शुरू की गई रेलवे परियोजनाएं	- भद्राचलम रोड-सत्तुपल्ली नई BG रेल लाइन - अंगुल - बलराम - पुतगड़िया - जरापाड़ा होते हुए पुतगड़िया से तेंतुलोई (68 किलोमीटर) (ओडिशा में MCRL रेल कॉरिडोर) तक का लिंक - टोरी-शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाइन - CERL (खरसिया-धरमजयगढ़ रेल लिंक) चरण-I

27. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare)

NFHS - 5 (2019-21)	- कम उम्र में होने वाले विवाह में कमी: 32 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कम उम्र में होने वाले विवाह में कमी देखी गई है। 25 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में NFHS-4 की तुलना में किशोर गर्भधारण के प्रसार में कमी देखी है। - कुल प्रजनन दर: TFR का स्तर NFHS-3 (2005 06) के 2.7 से घटकर NFHS-5 (2019-21) में 2.0 हो गया है जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 2.1 या उससे कम का प्रतिस्थापन TFR है।
G-20 के तहत की गई पहलें	डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (Global Initiative on Digital Health) - इसे G-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था। - इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों को एकजुट करने और तकनीकी उपकरणों तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए एक 'साझा मंच' तैयार करना है। डिजिटल स्वास्थ्य - भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य को अपनी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना है, जिसका नाम है- "UHC की सहायता करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान"।
तंबाकू के सेवन में रोकथाम	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) [COTP] संशोधन नियम, 2023 - तंबाकू उत्पादों या उनके उपभोग को प्रदर्शित करने वाले ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के सभी प्रकाशकों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा- - प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत और इसके मध्य में कम-से-कम तीस सेकंड की अवधि के लिए तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना होगा। - तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन या उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी को प्रदर्शित करना आवश्यक है।

	- कार्यक्रम के आरंभ और मध्य में, तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर न्यूनतम बीस सेकंड की अवधि का एक ऑडियो-विजुअल चेतावनी प्रदर्शित करना आवश्यक है। WHO का वैश्विक तंबाकू नियामक फोरम - अप्रैल 2023 में, मंत्रालय ने WHO के ग्लोबल टोबैको रेगुलेटर्स फोरम (GTRF) की सातवीं बैठक की मेजबानी की है। - ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र: मई 2023 में, इसे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) गतिविधियों की त्रैमासिक रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया। - तंबाकू मुक्त युवा अभियान: इसे विशेष रूप से युवाओं के बीच तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में गहन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
आयुष्मान भारत	घटक A - आयुष्मान आरोग्य मंदिर - आयुष्मान आरोग्य मंदिर: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs) का नाम बदलकर 'आरोग्यम परमं धनम्' टैग-लाइन के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। - मुख्य उपलब्धियां: 15 दिसंबर, 2023 तक 1,63,402 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन शुरू किया जा चुका है। घटक B - आयुष्मान भारत PM-JAY - सुर्खियों में रहीं संबंधित पहलें: - आयुष्मान भव पहल: गांवों को 'आयुष्मान ग्राम' का दर्जा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 'आपके द्वार आयुष्मान 3.0', 'आयुष्मान सभा', 'आयुष्मान मेला' सहित कई पहलें शुरू की गई हैं। - आपके द्वार आयुष्मान' (ADA 3.0) अभियान: इसे आयुष्मान भव अभियान के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा शुरू किया गया। 'आयुष्मान ऐप': प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीके प्रदान करने के लिए NHA ने एक नवीन मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए फेस-ऑथराइजेशन, OTP , IRIS और फिंगरप्रिंट आदि डेटा को दर्ज करता है। - मुख्य उपलब्धियां - इस योजना की शुरुआत से अब तक 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। - इस योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए AB PM-JAY के तहत कुल 26,901 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। - बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग 49% कार्ड महिलाओं से संबंधित हैं।
प्रतिरक्षा/ टीकाकरण	- राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 21 दिसंबर, 2023 तक, 97% से अधिक नागरिकों को COVID-19 टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 90% से अधिक पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। - अन्य पहलें - फ़ैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस (fIPV3) की तीसरी खुराक: यह 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। - पोलियो उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (SNID): 2023 में, 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 28 मई और 10 दिसंबर को 2 SNID आयोजित किए गए हैं। - सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0: 5 वर्ष तक के बच्चों और नियमित टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं के लिए एक कैच-अप टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।

	○ U-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म पायलट परियोजना: इसके तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन केस-आधारित ट्रेकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों हेतु पायलट मोड में शुरू किया गया है।
प्रधान मंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान	● पिछले 9 वर्षों में टी.बी. के मामलों में 16% की गिरावट (10% की वैश्विक गिरावट की तुलना में) और टी.बी. से होने वाली मौतों में 18% की गिरावट (10% की वैश्विक गिरावट की तुलना में) आई है। ○ टी.बी. के मामलों की रिपोर्टिंग: पिछले 9 वर्षों में टी.बी. के मामलों की समग्र रिपोर्टिंग में 64% की वृद्धि हुई है। ○ निजी क्षेत्रक द्वारा मामलों की रिपोर्टिंग: पिछले 8 वर्षों में निजी क्षेत्रक द्वारा मामलों की रिपोर्टिंग में 7 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ○ नवंबर 2023 तक, निजी क्षेत्रक द्वारा 7.3 लाख मरीजों (कुल का 32%) की रिपोर्टिंग की जा चुकी है। ○ मल्टी-ड्रग प्रतिरोधी टी.बी. के मामलों में नई टी.बी.-प्रतिरोधी दवाओं - बेडाक्विलिन, डेलामेनिड - का प्रयोग किया जाता है। ○ टी.बी. उपचार की सफलता की दर: पिछले 9 वर्षों में, यह कार्यक्रम 80% से अधिक की उपचार सफलता दर को बनाए रखने में सक्षम था। नवंबर 2023 तक, सफलता की यह दर 86.3% थी। ○ इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल-अप: पिछले 9 वर्षों में नामित माइक्रोस्कोपी सेंटर (DMCs) में 80% की वृद्धि हुई है। ○ दवा प्रतिरोधी टी.बी. उपचार केंद्रों की संख्या 2014 के 127 से बढ़कर 2022 में 792 हो गई।
राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम	● 2010 से 2022 के बीच HIV संक्रमण के वार्षिक मामलों में 42% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर गिरावट की औसत दर 38% थी। ● 2010 से 2022 के बीच एड्स से संबंधित मामलों में मृत्यु दर में 77% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक औसत 51% है। ● नई पहलें ○ रेड रन्स (RED RUNs): युवाओं को खुद को स्वस्थ रखने और उन्हें स्वस्थ विकल्प चुनने में सक्षम बनाने में मदद करने के लिए खेलों के जरिए जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार रेड रन्स का आयोजन किया गया था। ○ 'अब नहीं चलेगा' अभियान: इसका उद्देश्य HIV और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के समग्र कार्यान्वयन के तहत असमानता को कम करने तथा HIV से जुड़े कलंक को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना है। ○ एकीकृत अभियान (ISHTH: एकीकृत STI, HIV, टी.बी. और हेपेटाइटिस): जेलों और अन्य बंद स्थानों में कैदियों के बीच HIV, हेपेटाइटिस, सिफलिस और टी.बी. से पीड़ित कैदियों की पहचान करते हुए उन्हें देखभाल, सहायता तथा उपचार सेवाएं उपलब्ध कराना। ○ एकीकृत स्वास्थ्य अभियान (IHC): इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर क्षेत्र के समुदायों में HIV, सिफलिस, टी.बी. और हेपेटाइटिस की शीघ्र पहचान और उपचार के लिए की गई है।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)	● FSSAI द्वारा मिलेट्स कैलेंडर जारी किया गया। ● FSSAI ने ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का आयोजन किया। ○ प्रधान मंत्री ने FSSAI द्वारा तैयार "श्री अन्न - एक समग्र अवलोकन" नामक पुस्तक का डिजिटल रूप से विमोचन किया। यह FSSAI द्वारा मिलेट्स के तैयार किए गए मानकों पर आधारित एक पुस्तक है।

	- पहला वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2023 FSSAI द्वारा आयोजित किया गया था। - MoHFW ने 'SaNGRAH' (सेफ फूड्स फॉर नेशंस: ग्लोबल फूड रेग्युलेट्री हैंडबुक) की शुरुआत की है। - यह दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य विनियामक प्राधिकरणों, उन्हें सौंपे गए कार्यों, खाद्य संरक्षा परिवेश, खाद्य परीक्षण सुविधाओं, खाद्य अधिकारियों के संपर्क के विवरण का एक डेटाबेस है। - अक्टूबर 2023 में FSSAI के तत्वावधान में 'श्री अन्न' की थीम पर ईट राइट समिट 2023 का आयोजन किया गया। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा (फूड सेफ्टी) सूचकांक 2022-23 - इसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जून 2023 में जारी किया गया। - सूचकांक के प्रमुख बिंदु: - बड़े राज्यों में: केरल ने पहला स्थान हासिल किया। - छोटे राज्यों में: गोवा ने पहला स्थान हासिल किया। - केंद्र शासित प्रदेशों में: जम्मू-कश्मीर को पहला स्थान मिला।
विविध	- मलेरिया: देश में 2015 और 2022 के बीच मलेरिया रोग के मामलों में 85% और मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर में 78.38% की कमी आई है। - भारत में 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। - प्रसवोत्तर देखभाल दिशा-निर्देशों को अनुकूलित करना: इसे जून 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर जोर देकर प्रसवोत्तर देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही, ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाता है। - कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग सम्मेलन 2023 - FAO ने भारत को मसालों और खाद्य जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति के लिए मेजबान देश सचिवालय के रूप में मान्यता दी है। - आयोग ने मिलेट्स समूह के लिए वैश्विक मानक विकसित करने के भारत के प्रस्ताव पर भी विचार किया है।

28. आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH)

उपलब्धियां और विकास	- G-20 न्यू डेलही लीडर्स डिक्लेरेशन में पारंपरिक चिकित्सा को शामिल किया गया। - भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयुष के लिए समर्पित वर्टिकल तैयार किया गया है। - आयुर्वेद सूचना विज्ञान के मानकीकरण के लिए पारंपरिक दवाओं पर ISO TC 215 समर्पित कार्य समूह (WG 10) का गठन किया गया है। - गांधीनगर में आयोजित "पारंपरिक चिकित्सा पर WHO-FIRST वैश्विक शिखर सम्मेलन" के बाद गुजरात घोषणा-पत्र जारी किया गया। - गृह मंत्रालय द्वारा आयुष बीजा अधिसूचित किया गया है और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन-स्टॉप 'हील इन इंडिया' पोर्टल लॉन्च किया गया है। 'स्मार्ट' (स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स) को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (NCISM) और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद कॉलेजों तथा अस्पतालों के जरिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। - राष्ट्रीय आयुष मिशन: यह आयुष स्वास्थ्य देखभाल में अवसंरचना के विकास में केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। - आयुष मंत्रालय ने रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICD-11 के पारंपरिक चिकित्सा अध्याय के दूसरे मॉड्यूल में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां शामिल करने के लिए मानकीकृत कोड तैयार करने का समर्थन किया है।
---------------------	--

29. फार्मास्यूटिकल्स विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) {Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals and Fertilizers)}

प्रमुख उपलब्धियाँ	• प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत, सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10000 से अधिक रिटेल दुकानें खोली गई हैं। ○ वर्ष 2023 में, इन दुकानों के प्रोडक्ट बास्केट में 206 नई दवाएं और 13 सर्जिकल उपकरण शामिल किए गए हैं। ○ यह योजना फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत एक स्वायत्त सोसायटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। • भारत में क्रिटिकल प्रारंभिक सामग्रियों, औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (API) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना चलाई जा रही है। ○ इसके तहत 41 थोक दवाओं के पात्र निर्माताओं को आधार वर्ष के दौरान उनकी वृद्धिशील बिक्री पर छह वर्षों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। • केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना के रूप में 'फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करने की योजना' को निम्नलिखित उप-योजनाओं के साथ लागू किया गया है: ○ सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता (API-CF) ○ फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS) ○ फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना (PMPDS) • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ○ चिकित्सा उपकरणों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ○ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। ○ ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मामले में 74% से अधिक और 100% तक के निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। • चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी गई।
-------------------	---

30. रसायन और पेट्रोसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) {Department of Chemicals and Petrochemicals (Ministry of Chemicals and Fertilizers)}

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड	• टेक्निकल ग्रेड कीटनाशकों के लिए उनके फॉर्मूलेशन के साथ 14 नए HS कोड बनाए गए हैं। • कुल मिलाकर, 28 नए HS कोड बनाए गए हैं।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)	• BIS अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत जारी किया गया। • विभाग ने 61 QCO को अधिसूचित किया है, जिनमें से 30 को लागू किया जा चुका है। • 2023 के दौरान, 12 QCO लागू किए गए हैं।
'रसायन और पेट्रोकेमिकल्स' पर B-20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	• यह कार्यक्रम भारत की G-20 प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में "रसायन और पेट्रोकेमिकल्स: हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से संधारणीय रूपांतरण (Chemicals and Petrochemicals: Sustainable transitions through Green Technologies and digitalization)" विषय पर आयोजित किया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	रसायन क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।
इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नॉलजी (IPFT)	- व्हाइटफ्लाइज के खिलाफ प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए ओलेरेसिन के साथ इमिडाक्लोप्रिड नैनोसस्पेंशन फॉर्मूलेशन का विकास किया गया है। - मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए घुलनशील पॉलीमरिक फिल्म का विकास किया गया है। - बीजीय मसालों (Seed spices) को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैव-वानस्पतिक कीटनाशक (Bio-botanical pesticide) फॉर्मूलेशन का विकास किया गया है। - भिंडी की फसल पर इमिडाक्लोप्रिड, इमामेक्टिन बेंजोएट और डेल्टामेथ्रिन के नए फॉर्मूलेशन की जैव-प्रभावकारिता, पादप-विषाक्तता और प्राकृतिक शत्रुओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

31. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (Ministry of Food Processing)

बजट के माध्यम से क्षेत्रक आधारित सहायता	2022-23 में संशोधित अनुमान की तुलना में 2023-24 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के विकास के लिए 73% अधिक आवंटन किया गया है।
क्षेत्रक की उपलब्धियां	- कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2014-15 के 13.7% से बढ़कर 2022-23 में 25.6% हो गई है। - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक कुल पंजीकृत/ संगठित क्षेत्रक में लगभग 12.22% रोजगार प्रदान करता है।
सरकारी योजनाएं	प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) - PMKSY की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत कुल 1401 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। - कोल्ड चेन परियोजनाओं पर NABCON की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं: - स्वीकृत परियोजनाओं में से 70% के पूरा होने से मत्स्य पालन और डेयरी उत्पादों के मामले में अपशिष्ट की मात्रा क्रमशः 70% और 85% तक कम हुई है। प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PMFME) योजना - इस योजना के शुरू होने के बाद से, व्यक्तिगत लाभार्थियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उत्पादक सहकारी समितियों के लिए PMFME के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के तहत कुल 65,094 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। - एक जिला एक उत्पाद (ODOP) प्रोसेसिंग लाइनों और संबद्ध प्रोडक्ट लाइनों में 76 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) - यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि के लिए लागू की जा रही है। - PLISFPI की विभिन्न श्रेणियों के तहत अब तक कुल 176 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 22 MSME सहित 30 कंपनियां, मोटे अनाज पर आधारित उत्पादों के लिए PLI योजना (PLISMBP) के तहत मिलेट्स (मोटे अनाज या श्रीअन्न) आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने में शामिल हैं। - PLISMBP अनुमोदित खाद्य उत्पादों में न्यूनतम 15% मिलेट्स से जुड़ी सामग्री के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (IYM) - 2023	- PMFME योजना के तहत मिलेट्स उत्पादों वाले 19 जिलों को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के रूप में चिन्हित किया गया। - मिलेट्स उत्पादों के लिए 3 विपणन और ब्रांडिंग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। - मिलेट्स प्रसंस्करण लाइन्स वाले 10 राज्यों में 17 इनक्यूबेशन सेंटर्स को मंजूरी दी गई है।
वर्ल्ड फूड इंडिया, 2023	- इसके आयोजन ने उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, उपकरण विनिर्माताओं, लॉजिस्टिक्स कंपनियों आदि के बीच जुड़ाव और तालमेल के लिए सहायक मंच प्रदान किया। - इसने भारत को श्री अन्ना (मिलेट) की संभावनाओं सहित खाद्य प्रसंस्करण के लिए निवेश गंतव्य के रूप में भी प्रदर्शित किया।

32. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) {Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)}

खाद्य सुरक्षा एवं पी.डी.एस	81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योजना शुरू की गई है। - वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की एक पहल है। इसके तहत कोई भी लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न की डिलीवरी ले सकता है। - ONORC को सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जो लगभग 100% NFSA आबादी को कवर करता है। - गेहूं और आटे की कीमतों को कम करने के लिए एक ब्रांड के रूप में 'भारत आटा' की बिक्री NCCF, नेफेड द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत की जा रही है। - यह अधिकतम खुदरा मूल्य 27.50/किलोग्राम पर आटा बेचेगा। - सरकार ने लक्षित पीडीएस (TPDS) के माध्यम से और ICDS तथा पीएम पोषण जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। - TPDS में सुधार: - NFSA के तहत 100% डिजिटलीकृत राशन कार्ड लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध है। >99.8% राशन कार्डों की आधार सीडिंग की गई है। ~99.8% उचित मूल्य की दुकानें इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों द्वारा स्वचालित हैं।
अन्य पहल	- सरकार ने सभी राज्य खरीद पोर्टलों के एकीकरण द्वारा खरीद की एकल स्रोत जानकारी के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड पैरामीटर (MTP) की शुरुआत की है। - MTP में आधार सीडिंग के साथ किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, डिजिटलीकृत मंडी संचालन, किसानों को MSP हस्तांतरण आदि शामिल है। - समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने, जमाखोरी और अनुचित स्ट्रेबाजी को रोकने के लिए 'गेहूं स्टॉक सीमा' लागू की गई है। - निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWC) के माध्यम से भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना लागू की जा रही है। - उन्नयन और कमियों में सुधार के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद से FCI के स्वामित्व और किराये पर लिए गए गोदामों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जा रहा है।

	• भंडारण क्षेत्र ○ कवर और प्लिंथ को कवर्ड कैपेसिटी में परिवर्तित करना। ○ केंद्रीय पूल स्टॉक या CAP चरणबद्ध समाप्ति के लिए राज्यों द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण किया जा रहा है। ○ वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा गोदामों को मानकीकृत करने के लिए प्रमाणन किया जा रहा है। ○ पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों में भंडारण गोदामों के निर्माण की योजना लागू की जा रही है।
चीनी और इथेनॉल क्षेत्रक	• गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 5000 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ गया। • राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली द्वारा चीनी क्षेत्रक में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। • पिछले चीनी सीज़न का ~99.9% गन्ना बकाया चुका दिया गया है। • इथेनॉल ○ सरकार अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदलने के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहित कर रही है। ○ भारत सरकार पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। ▪ EBP कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।

33. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) {Department of Social Justice & Empowerment (Ministry of Social Justice & Empowerment)}

प्रमुख उपलब्धियां	• अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: 2023 के दौरान 22 दिसंबर, 2023 तक कुल 18,32,628 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति जारी की गई है। • अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस): इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है और योजना के तहत 44 नए संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे कुल संख्या 266 हो गई है। • प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY): 01 जनवरी, 2023 से अब तक कुल 3132 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: इसके तहत 2023 में लगभग 92093 अत्याचार पीड़ितों/ आश्रितों को राहत प्रदान की गई है। • मशीनीकृत स्वच्छता इको-सिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते/ NAMASTE): 27 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में सीवर और सेप्टिक थ्रमिकों की प्रोफाइलिंग के लिए नमस्ते मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। • प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पी.एम.-दक्ष): 2023-24 के दौरान, 28 सरकारी और 84 निजी प्रशिक्षण संस्थानों को योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। • ट्रांसजेंडर्स और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के कल्याण के लिए संशोधित योजना दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
-------------------	--

34. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) {Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Ministry of Social Justice & Empowerment)}

प्रमुख पहलें/ उपलब्धियाँ	• दिव्यांगता से जुड़े क्षेत्रक में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। • दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित सुधार अपनाए गए हैं;
--------------------------	--

	○ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में सार्वभौमिक सुगम्यता (Universal accessibility) से संबंधित पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (CoA) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ○ डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) पोर्टल के माध्यम से बिना किसी के नाम का उल्लेख किये हुए डेटा जारी किया गया। ○ हॉर्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स एंड स्पेस स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया-2021 जारी किया गया है। ○ ICT उत्पादों और सेवाओं के मामले में सुगम्यता/ एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित की गई है। ○ सुगम्य खेल परिसरों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ○ नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक-2022 जारी किए गए। • CSR के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सपोर्ट, एक्टिवेट एंड बिल्ड एस्योर्ड लाइवलीहुड (SABAL/ सबल) के लिए कॉर्पोरेट जगत के साथ गोलमेज बैठक आयोजित की गई। • आर्टिफिशियल लिंक्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALMICO) DEPwD के तत्वाधान में काम करता है। एलिम्को अपनी पहल प्रधान मंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDKs) के माध्यम से मुफ्त सहायता, उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करता है। इसके तहत प्रोस्थेसिस एवं ऑर्थोसिस फिटमेंट, ऑडियोमेट्री असेसमेंट और आफ्टर सेल सपोर्ट सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
--	---

35. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

प्रमुख उपलब्धियां	• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI): इनकी संख्या 10119 (वर्ष 2014) से बढ़कर 2022 में 14953 हो गई है, अर्थात् इसमें 47.77% की वृद्धि दर्ज हुयी है। • फ्लेक्सी-MoU योजना: प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) ने अग्रिवीरों के कौशल प्रमाणन के लिए 2022 में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • व्यावसायिक कौशल में महिलाओं की भागीदारी: शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS)/ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) के तहत सत्र 2023-24 के आगे भी महिला अभ्यर्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा के लिए शुल्क में छूट को मंजूरी दी गई है। • नई प्रौद्योगिकियां: DGT ने क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जैसी IT कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। • प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना: इसके लॉन्च के बाद से, 13 दिसंबर, 2023 तक लगभग 1.40 करोड़ अभ्यर्थियों को PMKVY के तहत प्रशिक्षित किया गया है। • प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (Apprenticeship Training): 29 नवंबर, 2023 तक 24,74,714 प्रशिक्षुओं का नामांकन हो चुका है। ○ स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए 6-12 महीने का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
नई पहलें	• पी.एम. विश्वकर्मा योजना ○ इस योजना का लक्ष्य आधुनिक बाजार के लिए आवश्यक कौशल वृद्धि हेतु व्यापक सहायता प्रदान करते हुए शिल्पकारों को प्रौद्योगिकी से लैस करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। ○ वर्तमान में, 18 ट्रेड (पेशे) इस योजना का हिस्सा हैं। • स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म: यह कौशल और नौकरियों पर केंद्रित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह डिजिटल जॉब एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है, जो नौकरी चाहने वालों को प्रासंगिक अवसरों के साथ सहजता से जोड़ता है।

- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0: इसके तहत युवाओं को इंडस्ट्री 4.0, AI, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, IoT और ड्रोन से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी की गई है। इसका नाम "उद्यमिता के लिए शिक्षा: छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी का सशक्तीकरण (Education to Entrepreneurship: Empowering a generation of students, educators and entrepreneurs)" है।
 - इसके तहत, 5 लाख उद्यमियों को अगले 3 वर्षों में मेटा द्वारा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग कौशल प्रदान किया जायेगा।

36. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

प्रमुख उपलब्धियां

- भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (Critical and Strategic Minerals) की पहली नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई।
- कानूनों में बदलाव:
 - खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत निम्नलिखित संशोधन किए गए:
 - गहराई में पाए जाने वाले (डीप-सीटेड) और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस जारी करने की शुरुआत की गई है।
 - अन्वेषण लाइसेंस धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉक्स को खनन पट्टे के लिए नीलाम किया जाएगा, जिससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।
 - निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
 - अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023:
 - उत्पादन पट्टे का आवंटन केवल प्रतिस्पर्धी बोली वाली नीलामी के जरिये किया जाएगा।
 - कंपोजिट लाइसेंस की शुरुआत की गई है।
 - उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण का प्रावधान हटा दिया गया है। इसकी अवधि MMDR अधिनियम की तर्ज पर 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
- MMDR अधिनियम की धारा 9 B राज्य सरकारों को खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण एवं लाभ के लिए काम करने तथा राज्य में DMF की संरचना एवं कार्यों के लिए नियम बनाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) स्थापित करने का अधिकार देती है।
 - DMF को खनन पट्टा धारकों के वैधानिक योगदान से वित्त-पोषित किया जाता है।
- खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए पेरू, मोजाम्बिक, बोलीविया जैसे देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठकें आयोजित होती हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
- G20, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) का गठन स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए किया गया था।
- भारत, खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) का 14 वां सदस्य बन गया है। MSP महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय साझेदारी है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है।
- खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) घरेलू बाजार के लिए लिथियम और कोबाल्ट की सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही, यह ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली में कुछ परियोजनाओं के साथ भी जुड़ रही है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने "भूकोष" के माध्यम से भूवैज्ञानिक जानकारी को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने के लिए ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम (OCBIS) पोर्टल शुरू किया है।

- भारतीय खान ब्यूरो (IBM) निम्नलिखित के माध्यम से संधारणीय विकास फ्रेमवर्क (SDF) को कार्यान्वित कर रहा है:
 - खानों की स्टार रेटिंग की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली,
 - खनन निगरानी प्रणाली (MSS),
 - माइनिंग टेनमेंट सिस्टम (MTS)

37. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

प्रमुख उपलब्धियां

- भारत में लगभग 66.71 लाख कि.मी. का सड़क नेटवर्क है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। विभिन्न श्रेणियों में सड़क नेटवर्क की लंबाई:
 - राष्ट्रीय राजमार्ग (NH): 1,46,145 कि.मी.
 - राज्य राजमार्ग: 1,79,535 कि.मी.
 - अन्य सड़कें: 63,45,403 कि.मी.
- मोबाइल एप्लिकेशन: राजमार्ग यात्रा - ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और NHAI वन-डिजिटल टूल को ऑन-साइट NH परियोजना निष्पादन के लिए लॉन्च किया गया है।
- वाहन और सारथी को 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (तेलंगाना को छोड़कर) के सभी RTO में लागू कर दिया गया है।
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए TOT मॉडल, InVIT मॉडल और SPV मॉडल के माध्यम से प्रतिभूतिकरण (Securitization) का उपयोग किया जाता है।
- नागरिक-केंद्रित उपाय
 - भारत सीरीज़ का दायरा बढ़ाया गया।
 - रियल ट्राइविंग एमिशन (RDE) विनियम (यूरोप की तर्ज पर) को लाया गया है।
 - भारत पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2023 के जरिये पर्यटक वाहनों की सुगम आवाजाही को और आसान बनाया गया है।
 - बसों में फायर अलार्म सिस्टम (FAS) और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम (FPS) लगाए गए हैं।
 - पूरी तरह से निर्मित वाहनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने हेतु सुविधा प्रदान की गई।
 - यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग और उपभोक्ताओं को तथ्य एवं साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
 - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यवार वाहन ट्रेकिंग प्लेटफॉर्म का विकास (निर्भया फ्रेमवर्क के तहत) किया गया है।
 - RVSF पोर्टल: NIC ने वाहन पर एक मॉड्यूल विकसित किया है जिसके माध्यम से वाहन मालिक पुराने वाहनों को स्कैप करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
- यूटिलिटी कॉरिडोर
 - वित्त वर्ष 2024-25 तक 10,000 कि.मी. ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) बिछाने का कार्य, NHAI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

38. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) {Department of Drinking Water and Sanitation (Ministry of Jal Shakti)}

प्रमुख उपलब्धियां

- जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2023 तक लगभग 14 करोड़ ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं।
- भारत में 90% गांवों को स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के तहत ODF-प्लस घोषित किया गया है (03 जनवरी, 2024 तक)।

- ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के संचालन हेतु सुजलाम- 1, 2 और 3 अभियान शुरू किए गए।
- **रेट्रोफिट टू दिवन पिट अभियान (2022):** इसे सिंगल पिट शौचालय को दिवन पिट शौचालय में तब्दील करने की सरल ऑन-साइट पद्धति के माध्यम से मल-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

39. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) {Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Ministry of Jal Shakti)}

हासिल उपलब्धियां और प्रगति

- दुबई में आयोजित COP-28 के दौरान भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस 2023 को लॉन्च किया गया।
- राष्ट्रीय जल मिशन का जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2023 अभियान के तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं; पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं और वाटरशेड विकास संरचनाओं के निर्माण के काफी लाभ हुआ है।
- **असेसमेंट ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट**
 - कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) है;
 - निकासी योग्य वार्षिक भूजल संसाधन 407.21 BCM है;
 - वार्षिक भूजल निकासी 241.34 BCM है।
- जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार के लिए जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE) की स्थापना की गई।
- **केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP):** यह केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) द्वारा क्रियान्वित नदियों को आपस में जोड़ने वाली पहली परियोजना है।
- केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने 2023 के दौरान रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जलाशयों में अवसादन की स्थिति का आकलन किया है।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM): इसका उद्देश्य खेत में पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है।
- **अटल भूजल योजना (अटल जल):** यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य जल संकट वाले निर्धारित क्षेत्रों में संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है।
- **सिंचाई गणना (Irrigation Census):** देश के ग्रामीण और शहरी सभी जल निकायों को कवर करते हुए जल निकायों की पहली गणना तथा संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए छठी लघु सिंचाई गणना पूरी हो चुकी है।

40. पत्तन, पोत-परिवहन और जल-मार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports Shipping and Waterway)

प्रमुख उपलब्धियां

विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) रिपोर्ट - 2023

- भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 44वें स्थान पर था।
- औसत कंटेनर ड्वेल टाइम केवल 3 दिनों के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए यह 4 दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 7 दिन और जर्मनी के लिए 10 दिन है।
- भारतीय बंदरगाहों का टर्नअराउंड टाइम 0.9 दिन तक हो गया है।

नई पहलें

- **मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047:** इसे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (GMIS), 2023 में लॉन्च किया गया। यह मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है।

	○ इसका उद्देश्य भारत की ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करते हुए विश्व स्तरीय बंदरगाहों को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय पोत-परिवहन और संधारणीय समुद्री क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। ● राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री): यह लॉजिस्टिक्स जगत के सभी हितधारकों को जोड़ने वाला वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। ○ NLP में जलमार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग सहित परिवहन के सभी माध्यमों को कवर किया गया है। यह एक सुगम एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स सेवा कवरेज प्रदान करता है। ● सागरमंथन-व्यापक निगरानी डैशबोर्ड: परियोजनाओं, KPI, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और वित्तीय एवं परिचालन मापदंडों की निगरानी के लिए एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। ● सागर-सेतु: इसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री) द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है। इसका उद्देश्य व्यापार करने की सुगमता को और बेहतर बनाना है। ● 'हरित सागर'- ग्रीन पोर्ट दिशा-निर्देश 2023: इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। ● कोलकाता में ग्रीन हाइड्रोजन हब: NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) ने कोलकाता में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए "श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता" के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अन्य प्रमुख पहलें	● नैशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग (NCoEGPS): देश ने में पहले NCoEGPS का उद्घाटन किया गया। ● भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर: भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर, कोस्टा सेरेना को मुंबई में लॉन्च किया गया। ● सागर संपर्क: यह एक स्वदेशी डिफ्रेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (DGNSS) है। यह पोत की सटीक स्थिति के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों को ठीक करता है, जिससे बंदरगाहों पर दुर्घटनाओं में कमी आती है। ● सागर में सम्मान: यह समुद्री क्षेत्रों में महिला नाविकों की भूमिका को बढ़ावा देने वाला एक अभियान है। ● अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC): इसका उद्देश्य भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) विकसित करना है। यह कार्य राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी से किया जायेगा। ● समृद्धि-ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली: यह प्रमुख बंदरगाहों, आदि पर ड्रेजिंग गतिविधियों की निगरानी को बेहतर बनाएगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.